सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 133, नई दिल्ली । बुधवार, 24 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने किरदार की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिये, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है।

03 बजट:2024, रोजी-रोटी और राजनीति का कॉकटेल
06 अर्थव्यवस्था को तीव्र गति एवं महाशक्ति बनाने वाला बजट
08 तकनीकी आजादी की ओर बढ़े भारत

सार्वजनिक परिवहन को मिला बूस्टर डोज, मिलेगी रफ्तार

बजट में पुरानी योजनाओं को पूरा करने पर जोर एनसीआरटीसी को 3596 करोड़ मिले, मेट्रो फेज चार का बढ़ेगा नेवटर्क

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की मौजूदा योजनाओं को पूरा करने के साथ ही विस्तार देने के लिए केंद्रीय बजट में खास ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार ने बजट में दिल्ली-एनसीआर के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली कोई नई योजना भले ही घोषित नहीं की है, लेकिन पुरानी योजनाओं को रफ्तार देने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरीडोर (एनसीआरटीसी) और मेट्रो योजनाओं को अलग-अलग बजट का आवंटन किया है। इससे दिल्ली से हरियाणा के बीच आवाजाही आसान होगी।

केंद्र सरकार का एनसीआरटीसी की दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ योजना को पूरा करने पर जोर है। साथ ही दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी तक की परियोजना के लिए लगातार

दूसरे साल 3596 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। मेरठ से दिल्ली के बीच 82.15 किलोमीटर का कॉरीडोर है। अभी तक इसके एक हिस्से पर परिचालन शुरू हुआ है। इस साल के अंत तक दिल्ली तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार ने देशभर में मेट्रो योजनाओं के विस्तार के लिए बजट के आवंटन में करीब एक हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके बाद उम्मीद है कि दिल्ली मेट्रो के विस्तार की मौजूदा योजनाओं को भी रफ्तार मिलेगी। मेट्रो फेज चार में लंबे समय से इंतजार कर रही नरेला- बवाना कॉरीडोर को अब कुंडली तक ले जाने की योजना तेजी से आगे बढ़ेगी।

एनसीआरटीसी को मिला बजट

3596 करोड़ रुपये नमो भारत के लिए मिला।

82 किलोमीटर लंबा है दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर (निर्माणाधीन)

164 किलोमीटर लंबा होगा दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी (प्रस्तावित)

मेट्रो

21,335 करोड़ रुपये देशभर में मेट्रो के लिए आवंटित

मंत्री आतिशी बोलीं- केंद्र को 2.5 लाख करोड़ का कर देती है दिल्ली, फिर भी बजट में मिला सिर्फ धोखा

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज यानी मंगलवार (23 जुलाई) को पेश कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार का यह 11वां बजट है। बजट को लेकर दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने बड़ा बयान दिया है।

मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली करीब 2.5 लाख करोड़ का कर केंद्र को देती है। दिल्ली को इस साल 10,000 करोड़ केंद्रीय कर और 10,000 करोड़ एमसीडी के लिए मिलना चाहिए। दिल्ली 2.07 करोड़ केंद्रीय कर और 25,000 करोड़ जीएसटी भरता है। केवल दिल्ली के अलावा हर राज्य को कर (टैक्स) का शेयर वापस मिलता है। आतिशी ने कहा, हमें उम्मीद थी, इस साल दिल्ली के लोगों को उनका शेयर मिलेगा।' आतिशी ने कहा कि केंद्रीय बजट में एक बार फिर दिल्लीवालों को धोखा मिला है। इस 2024-25 के बजट में 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये देश के विभिन्न राज्यों को दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली वालों को इसमें से एक रुपये भी नहीं मिला है। वहीं, देश की विभिन्न स्थानीय निकायों को 82207 करोड़ रुपये दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एक रुपये इस बजट में नहीं मिला है। दिल्ली ने केंद्र सरकार को पिछले साल 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपये आयकर और 25 हजार करोड़ रुपये सीजीएसटी के रूप में दिये। यानी कुल मिलाकर 2 लाख 32 हजार करोड़ का कर दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली को इस बजट में कुछ नहीं दिया गया है।

आतिशी ने कहा, 'मोदी सरकार के बजट में दिल्ली की जनता को मिले शून्य रुपये मिले हैं। दिल्ली के लोगों की केंद्र सरकार से मांग थी कि उनके द्वारा कर के रूप में दिए जाने वाले पैसे का 5% हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्लीवालों की मांग पूरी नहीं की है। केंद्र सरकार स्थानीय निकाय को आर्थिक सहायता देती है, उसी तरह दिल्ली के लोग भी अपने कर का 5% हिस्सा एमसीडी को देने की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने एक रुपया भी नहीं दिया है।' आतिशी ने कहा, 'दिल्ली के लोग हर वर्ष दिल्ली सरकार को 40 हजार करोड़ का कर देते हैं। इस 40 हजार करोड़ के कर से केजरीवाल सरकार दिल्लीवालों को बेहतरीन सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, 24 घंटे मुफ्त बिजली और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा समेत कई सुविधाएं देती है।' वहीं, दिल्ली के ही लोग भाजपा शासित केंद्र सरकार को

रेलवे यात्रियों की सुरक्षा पर खर्च होगा बजट का बड़ा हिस्सा

राजधानी में रेलवे से संबंधित विकास कार्यों एवं सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 2577 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मंगलवार को बजट पेश होने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बार बजट का एक बड़ा हिस्सा विकास कार्यों के साथ सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। राजधानी में नई दिल्ली, बिजवासन, सफदरजंग रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। वहीं, अमृत भारत योजना के तहत सब्जी मंडी, दिल्ली कैंट और होलंबी कला स्टेशन का विकास किया जा रहा है। रेलवे को मिले बजट से इन परियोजनाओं में तेजी आएगी।

सूत्रों ने बताया कि बजट में मिली राशि से दिल्ली-अलवर के बीच 104 किलोमीटर का नया ट्रैक बनाया जाएगा। नई दिल्ली से तिलक ब्रिज के बीच पांचवीं एवं छठी लाइन बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई 2.65 किलोमीटर है। दिल्ली से सहारनपुर बाईपास के बीच भी 175 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा। दया बस्ती पर ग्रेड सेपरेटर के अलावा तुगलकाबाद से लेकर पलवल तक चौथी लाइन बिछाई जाएगी।

गडकरी के सड़क परिवहन को मिला सबसे अधिक पैसा जाने किस मंत्रालय को आवंटित हुआ कितना बजट

संजय बाटला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. सरकार ने सड़क परिवहन मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया है. जानें किस मंत्रालय को मिला सबसे अधिक बजट

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में देश का आम बजट पेश कर दिया है. यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है. इस बार सरकार ने कई बड़े एलान किए. सरकार ने मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है. सरकार ने विभिन्न सैक्टरों के लिए एलान किए हैं, जैसे- सड़क, रक्षा, कृषि आदि. लेकिन क्या आप जानते हैं, सरकार ने सबसे अधिक बजट किस मंत्रालय को दिया है. आइये जानते हैं, बजट में सरकार ने किस मंत्रालय को कितना बजट दिया'

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मंत्री- नितिन गडकरी

बजट 2024-2025 में सरकार ने सबसे अधिक पैसा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दिया है. यह मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है. गडकरी के परिवहन मंत्रालय को सबसे अधिक 5,44,128 करोड़ रुपये आवंटित किया है.

रक्षा मंत्रालय, मंत्री- राजनाथ सिंह

सडक परिवहन मंत्रालय के बाद सबसे अधिक बजट रक्षा मंत्रालय को मिला है. यह बजट राजनाथ सिंह के पास है. विभाग को 4.54 लाख करोड़ रुपये दिए हैं.

ग्रामीण विकास मंत्रालय, मंत्री- शिवराज सिंह चौहान

सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2,65,808 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

कृषि मंत्रालय, मंत्री- शिवराज सिंह चौहान

सरकार ने कृषि मंत्रालय को 1,51,851 करोड़ रुपये आवंटित किया है.

गृह मंत्रालय, मंत्री- अमित शाह

सरकार ने गृह मंत्रालय को 1,50,983 करोड़ रुपये आवंटित किया है.

शिक्षा मंत्रालय, मंत्री- धर्मेंद्र प्रधान

सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को 1,25,638 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

आईटी और दूरसंचार मंत्रालय, मंत्री- ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया

सरकार ने आईटी और दूरसंचार मंत्रालय को 1,16,342 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय, मंत्री- जेपी नड्डा

सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,287 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

शहरी विकास मंत्रालय

सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय को 82,577 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

उर्जा मंत्रालय

सरकार ने उर्जा मंत्रालय को 68,769 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

चुनावी वादे को पूरा करेगी सरकार, नेशनल हाईवे पर लंबी दूरी के ट्रक चालकों के लिए जल्द शुरू करेगी यह योजना

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार ने भाजपा द्वारा किए गए चुनावी वादे को पूरा करते हुए राजमार्गों (हाईवे) के किनारे लंबी दूरी के ट्रक चालकों के लिए लगभग 900 विश्राम केंद्र (रेस्ट सेंटर) उपलब्ध कराने की योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है।

नई दिल्ली: सरकार ने भाजपा द्वारा किए गए चुनावी वादे को पूरा करते हुए राजमार्गों (हाईवे) के किनारे लंबी दूरी के ट्रक चालकों के लिए लगभग 900 विश्राम केंद्र (रेस्ट सेंटर) उपलब्ध कराने की योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है। पेट्रोल पंपों के किनारे और हाईवे एजेंसियों द्वारा विकसित किए जा रहे वेसाइड एमेनिटीज (डब्ल्यूएसए) पर स्थित विश्राम स्थलों में शयनगृह, खुद-कपड़े धोने की सुविधा और खाना पकाने के क्षेत्र होंगे। ये सभी बहुत ही किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि विश्राम स्थलों में 10-50 बिस्तरों वाले शयनगृह होंगे। जिनमें चालकों और सहायकों के लिए चिकित्सा सहायता सहित सभी सुविधाएं होंगी। इनमें से ज्यादातर सुविधाएं तेल विपणन कंपनियों द्वारा विकसित पेट्रोल पंपों के पास होंगी। राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे डब्ल्यूएसए में लगभग 300 विश्राम स्थल शामिल होंगे। इन सभी विश्राम स्थलों के अगले 3-4 वर्षों में चालू होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम और सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना पर एक विस्तृत प्रस्तुति की समीक्षा की है। जिसे पीएमओ सहित विभिन्न स्तरों पर कई परामर्शों के बाद तैयार किया गया है। अच्छी और सस्ती आराम सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण लंबी दूरी के ड्राइवरों को ट्रक के केबिन में सोना पड़ता है और कभी-कभी सड़क के किनारे ही अपना खाना पकाना पड़ता है। नाकाफी आराम और थकान हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण रहे हैं।

भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा था, "हम ट्रक ड्राइवरों के लिए एक नई योजना शुरू करेंगे जिसके तहत नेशनल हाईवे पर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।"

इस साल की शुरुआत में, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में बोलते हुए पीएम मोदी ने एलान किया था कि नेशनल हाईवे नेटवर्क पर ड्राइवरों के लिए भोजन, साफ पीने का पानी, शौचालय, पार्किंग और आराम की सुविधाओं के साथ आधुनिक इमारतों को विकसित करने की नई योजना पर काम चल रहा है।

उन्होंने कहा, "ड्राइवर मोबिलिटी सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा हैं, जो हमारे ट्रकों, टैक्सियों को चलाते हैं। वे लंबे समय तक गाड़ी चलाते हैं। उनके पास आराम करने का समय नहीं है। वे सड़क दुर्घटनाओं के भी शिकार होते हैं। हम उनकी चिंताओं को समझते हैं... यह (आराम केंद्रों की स्थापना) ड्राइवरों को 'यात्रा को आसान बनाने' में भी सक्षम बनाएगा।"

ऑटो उद्योग निर्माताओं ने कहा कि लिथियम, कोबाल्ट पर सीमा शुल्क छूट से इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की वृद्धि को मिलेगा बढ़ावा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ऑटो उद्योग निर्माताओं के अनुसार केंद्रीय बजट 2024-25 में लिथियम, कोबाल्ट और अन्य दुर्लभ खनिजों पर प्रस्तावित सीमा शुल्क छूट से बैटरी उत्पादन लागत में कमी आने की उम्मीद है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन अधिक किफायती हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट और दो अन्य पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में कमी की घोषणा की।

सियाम के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लिथियम और कोबाल्ट आयात पर सीमा शुल्क छूट के साथ-साथ ली-आयन सेल पर रियायती सीमा शुल्क को मार्च 2026 तक बढ़ाने से भारतीय ऑटो उद्योग में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ई-लेनदेन पर 2% इक्वलाइजेशन लेवी को वापस लेने को भी सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये के उदार आवंटन का स्वागत किया, जिससे उन्हें विश्वास है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सियाम कौशल और कौशल उन्नयन पहलों और एमएसएमई के लिए समर्थन के बजट प्रस्तावों का भी समर्थन करता है, जिनमें से कई ऑटो क्षेत्र के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।

एक्मा की अध्यक्ष श्रद्धा सूरी मारवाह ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क कम करने से भारत में सेल निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान मिलेगा।

डेलॉइट इंडिया के पार्टनर रजत महाजन ने कहा कि यह कदम कुछ कंपनियों को भारत में बैटरी उत्पादन को स्वदेशी बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। रजत महाजन ने बताया कि बजट में ऑटोमोटिव क्षेत्र को कोई सीधा लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा, ₹उद्योग को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से फेम-3 सब्सिडी के संबंध में कुछ घोषणाओं की उम्मीद थी।₹

बैटएक्स एनर्जीज के सह-संस्थापक और सीईओ उत्कर्ष सिंह ने उल्लेख किया कि बीसीडी को कम करने और 25 आवश्यक खनिजों को कस्टम शुल्क से छूट देने से बैटरी निर्माण लागत कम होगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन अधिक किफायती बनेंगे।

हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी चेयरमैन पवन मुंजाल ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में भारत को प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया है जो सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

अशोक लीलैंड के कार्यकारी चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने कहा कि दुर्लभ खनिजों पर शुल्क कम करने से सतत गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ संतोष अय्यर ने कहा कि वे बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर दीर्घकालिक कम जीएसटी के लिए जीएसटी की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जलवायु वित्त वर्गीकरण विकसित करना जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।

टीवीएस मोटर कंपनी के एमडी सुदर्शन वेणु ने जोर देकर कहा कि मजबूत बुनियादी ढांचे का

रोलआउट अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव के साथ सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है।

स्विच मोबिलिटी के सीईओ महेश बाबू ने माना कि केंद्रीय बजट 2024 में फेम 3 जैसी कोई प्रत्यक्ष ईवी योजना नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो भारत के ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचा सकते हैं।

बैनएंड कंपनी के पार्टनर महादेवन सीतारामन ने कहा कि सीमा शुल्क छूट जैसी नियामक सहायता महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत महत्वपूर्ण बैटरी कच्चे माल के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

वार्डविज़ार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यतिन गुप्ते ने अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मजबूत वित्तीय सहायता की सराहना की और इसे ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बढ़ावा बताया।

क्वांटम एनर्जी के प्रबंध निदेशक चक्रवर्ती सी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए पूंजी और कौशल की आवश्यकता होती है, दोनों को इस बजट में संबोधित किया गया है।

न्यूरॉन एनर्जी के सीईओ और सह-संस्थापक प्रतीक कामदार ने कहा कि लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट देने से बैटरी सेल उत्पादन लागत कम होगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन अधिक किफायती बनेंगे।

ओमेगा सेकी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष उदय नारंग ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित करने और महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए पर्याप्त आवंटन की प्रशंसा की।

केंद्रीय बजट 2024-25 के रणनीतिक निर्णय उत्पादन लागत को कम करके और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर भारत के ईवी बाजार को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं। बुनियादी ढांचे के विकास और विभिन्न क्षेत्रों के लिए समर्थन के माध्यम से आर्थिक विकास पर जोर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का संकेत देता है। भाड में जाए जनता की अलख उठाए वसूली जारी है। ऐसे में ये समझ नहीं आता कि सडक सुरक्षा के लिए आम जनता को या ट्रैफिक पुलिस को जागरूक किया जाए? बहरहाल दैनिक परिवहन विशेष अखबार की सडक सुरक्षा मुहिम के लिए तमाम यातायात से पीडित नागरिक आपकी मुहीम साथ-साथ है।

आधी आबादी की अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी भागीदारी महिला संचालित विकास को मिलेगा

बजट में वूमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक रुपये के आवंटन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना और महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाएंगे।

मोदी सरकार का शुरू से मानना रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को पंख लगाने और जीडीपी को दहाई अंकों में पहुंचाने के लिए महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना और कार्यबल में उनकी भागीदारी जरूरी है। सरकार की यह सोच इस बजट में भी दिखाई देती है।

महिला संचालित विकास को बढ़ावा

बजट में वूमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक रुपये के आवंटन की व्यवस्था की गई है। साथ ही कामकाजी महिलाओं की जिंदगी आसान करने के लिए सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है।

मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि कामगारों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। इन सुविधाओं से कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी बढ़ेगी।

इसके अलावा महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना और महिला स्वयं सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाएंगे।

तीन लाख करोड़ से अधिक के आवंटन की व्यवस्था

मोदी सरकार शुरू से वूमेन लेड डेवलपमेंट की बात करती रही है बजट में भी यह दिखाई देता है। इसे बढ़ावा देने के लिए बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक के आवंटन की व्यवस्था की गई है।

यह आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की ओर संकेत करता है। महिलाओं के सशक्तीकरण और उन्हें अचल संपत्ति की मालकिन बनने को प्रोत्साहन देने की भी एक नीति बजट में दी गई है।

स्टांप शुल्क कम करने की सिफारिश

बजट में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों में स्टांप शुल्क कम करने पर विचार किया जाए इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करेगी। हालांकि महिला एवं बालविकास मंत्रालय के कुल बजट में खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। पिछले 2023-24 के बजट में इस मंत्रालय का बजट 25448.68 करोड़ रुपये था जो कि इस बार बढ़ा कर 26092.19 कर दिया गया है।

बजट में महिलाओं, युवाओं और नौकरीपेशा को क्या मिला? आसान भाषा में समझें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. बजट में हर वर्ग को सहूलियत देने का प्रयास किया गया है. खासतौर ये युवाओं, महिलाओं और नौकरीपेशा के लिए विशेष ऐलान किए गए हैं. सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर रखा गया है.

आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर नौकरी पेशा को राहत देने की कोशिश की है, तो युवाओं और महिलाओं के लिए भी कई अहम ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने एजुकेशन लोन का 3 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा उठाने की घोषणा की है, तो मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का ऐलान कर दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. बजट में हर वर्ग को सहूलियत देने का प्रयास किया गया है. बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री ने गरीब, महिला, युवा एवं अन्नदाता पर फोकस होने की बात कही थी. बजट में ये नजर भी आया. खास तौर से युवाओं, महिलाओं और नौकरीपेशा लोगों को सीधे लाभ देने का प्रयास किया गया है. आइए समझते हैं कैसे?

बजट में युवाओं के लिए क्या?

ऐसे युवा जिन्होंने किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें देश के किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा. इसका 3 प्रतिशत पैसा सरकार देगी. इसके लिए सरकार ई वाउचर्स की व्यवस्था करेगी जो हर साल तकरीबन एक लाख छात्रों को दिए जाएंगे.

स्वरोजगार के लिए युवा अब 20 लाख रुपये तक मुद्रा लोन ले सकेंगे. अब तक यह सीमा 10 लाख रुपये तक ही थी.

पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी. इन्हें हर माह 5000 रुपये भत्ता और 6000 रुपये सहायता भी दी जाएगी.

5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है.

1000 आईटीआई को हब और स्पोक व्यवस्था के परिणाम के साथ हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा.

मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकारी प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख तक ऋण की सुविधा दी जा सके.

महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या?

बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. इससे महिलाओं से संबंधित योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा.

बजट में महिलाओं का कार्यबल बढ़ाने पर फोकस किया गया है. इसके लिए वित्त मंत्री ने इसके लिए अलग से प्रयास करने की घोषणा की है.

उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों का निर्माण का ऐलान किया जाएगा. इसके अलावा शिशु होम भी बनाए जाएंगे.

नौकरीपेशा के लिए ये ऐलान

बजट में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होने पर 15 हजार रुपये की मदद तीन किस्तों में मिलेगी. ये लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये प्रतिमाह से कम है.

ये 13 सुपरफूड्स महिलाओं को हर उम्र में रखेंगे स्वस्थ, नहीं होगी खून की कमी, मोटापा से फिगर नहीं होगा बेडौल, देखें लिस्ट

महिलाएं अक्सर अपनी सेहत, खानपान आदि का ख्याल नहीं रखती हैं. यदि आप घर और ऑफिस के कामों के बीच खुद की सेहत को इग्नोर कर रही हैं तो इससे आप कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिर सकती हैं. हम आपको 13 ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बता रहे हैं, जो टीनएज गर्ल्स से लेकर मेनोपॉज की अवस्था में पहुंच चुकी हर महिला के लिए है बेस्ट.

महिलाएं अपने घर और ऑफिस के काम और फैमिली का ख्याल रखने में इतनी व्यस्त रहती हैं कि खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं. कभी भी खाती हैं, कुछ भी खा लेती हैं, नींद 7-8 घंटे नहीं लेती हैं. एक्सरसाइज करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाती हैं. अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आपकी सेहत के लिए ये ठीक नहीं है. आप 30-35 की उम्र में ही कई समस्याओं से ग्रस्त हो सकती हैं. आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्किन और हेयर संबंधित समस्याएं शुरू हो सकती हैं. कम उम्र में ही आपके चेहरे पर बुढ़ापा नजर आ सकता है. ऐसे में आप अपने लिए समय निकालें और 30 मिनट ही सही, एक्सरसाइज करें. बैलेंस डाइट लें. प्रॉपर नींद लें. जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख सकेंगी.

हेल्दी डाइट है बेहद जरूरी

खुद को हेल्दी रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी डाइट में कुछ सुपरफूड्स को शामिल करें. आयुर्वेदिक डॉक्टर दीक्षा भावसर (Dr. Dixa Bhavsar) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि कुछ सुपरफूड्स ऐसे हैं जो हर महिला के जीवन में गेम चेंजर की तरह साबित हो सकते हैं. फिर चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों न हो. ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो टीनएज लड़कियों से लेकर मेनोपॉज की उम्र या उससे भी आगे की हर उम्र की महिलाओं के लिए बेहद आवश्यक, फायदेमंद और जरूरी हैं. ये फूड्स आपको एनीमिया, पीसीओएस, थायरॉएड, नींद से संबंधित समस्या, खराब पाचन आदि समस्याओं से छुटकारा दिलाने में बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

महिलाओं के लिए 13 हेल्दी फूड्स

1. आंवला- आंवला में मौजूद विटामिन सी बालों और त्वचा की समस्या ओं (एंटी ऑक्सीडेंट होता है) को रोकता है. शरीर में ऊर्जा के स्तर में सुधार करता है. यह आयरन को अवशोषित करने में भी मदद करता है, जो हार्मोनल संतुलन के लिए जरूरी है. फल, पाउडर, जूस, कैंडी आदि के रूप में आप आंवले का सेवन कर सकती हैं.

2. अनार- हार्ट की समस्याओं से बचे रहने के लिए आप अनार खाएं. साथ ही अनार प्रजनन क्षमता और आंतों के लिए भी बढ़िया फल है. इसके फायदे पाने के लिए आप सप्ताह में एक/दो बार इसका सेवन करें.

3. पपीता- इसमें मौजूद लाइकोपीन सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम कर सकता है. आप पपीते का सेवन सप्ताह में एक/दो बार जरूर करें.

4. कद्दू के बीज- मैग्नीशियम से भरपूर महिलाओं को होने वाली कॉमन हेल्थ प्रॉबलम्स को दूर रखने के साथ ही मासिक धर्म में ऐंठन और पीएमएस के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है.

5. तिल – तिल का सेवन करने से आपके बाल और हड्डियों की सेहत लंबी उम्र तक दुरुस्त बनी रहेगी.

6. सूरजमुखी के बीज- एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को संतुलित करते हैं. इसे आप पुडिंग, सूप, सलाद, स्मूदी आदि में रोस्ट करके सेवन कर सकती हैं. इन सभी बीजों जैसे कद्दू, तिल, सूरजमुखी के बीजों को प्रतिदिन 1 चम्मच सेवन कर सकती हैं.

7. किशमिश – इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम और विटामिन डी होता है, जो हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं. साथ ही शरीर में आयरन की कमी भी नहीं होती है. बेस्ट तरीका है कि आप रात भर 5 किशमिश पानी में भिगोई हुई प्रतिदिन खा सकती हैं.

8. रागी- आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है, जो बेहद पौष्टिक है. रोजाना मुट्ठी भर रागी (Ragi) का सेवन किया जा सकता है.

9. खजूर – इसके सेवन से आपको पेट भरे होने का अहसास होता है, जिससे आप अत्यधिक खाने से बची रह सकती हैं. इस तरह वजन कंट्रोल में रहेगा. आप रोजाना 2-3 खजूर खा सकती हैं.

10. शतावरी- गर्भावस्था, स्तनपान, रजोनिवृत्ति और यहां तक कि प्रजनन क्षमता के लिए बेहतरीन जड़ी बूटी है शतावरी. महिलाएं शतावरी का सेवन पाउडर, दाने या घी के रूप में कर सकती हैं.

11. अखरोट- इसमें अल्फा-लिनोलेनिक एसिड (एएलए) होता है, जो एक ओमेगा-3 एसिड है. इसके सेवन से सूजन को कम करने के में मदद मिलती है. आप रोजाना 3-5 रात भर भिगोए हुए अखरोट खा सकती हैं.

12. पिस्ता- इनमें एंटीऑक्सिडेंट और फाइटो-केमिकल होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करते हैं. इससे आप जल्दी-जल्दी बीमार नहीं होंगी, इंफेक्शन और रोगों से भी बचाव होगा. आप रोजाना मुट्ठी भर पिस्ता खा सकती हैं.

13. घी- शतावरी के बाद महिलाओं के लिए दूसरा सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ है घी. यह उम्र बढ़ने (delays ageing) में देरी करता है. अंडे की क्वालिटी, पाचन, बाल और त्वचा की सेहत में सुधार करता है. आप घी को डाइट में सीमित मात्रा में जरूर शामिल करें.

बरसात में गर्भवती महिलाओं को जोखिम अधिक..! शिशु की सेहत पर भी पड़ सकता असर, इन 5 तरीकों से रखें खुद का ख्याल

गर्मी के बाद ये मौसम जितना सुहावना लगता है, उतना ही जोखिम भरा भी होता है. वैसे तो यह मौसम में सभी के लिए घातक है. लेकिन, गर्भवती महिलाओं के लिए ये अधिक जोखिम भरा हो सकता है. इतना ही नहीं पेट में पल रहे बच्चे की सेहत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं कि खुद का कैसे रखें ख्याल-

गर्मी के बाद मानसून अपने मजबूत कदम जमा चुका है. ऐसे में खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. क्योंकि, गर्मी के बाद ये मौसम जितना सुहावना लगता है, उतना ही जोखिम भरा भी होता है. वैसे तो यह मौसम में सभी के लिए घातक है. लेकिन, गर्भवती महिलाओं के लिए ये अधिक जोखिम भरा हो सकता है. इतना ही नहीं पेट में पल रहे बच्चे की सेहत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है.

डॉक्टर्स की मानें तो बरसात में जुकाम, फ्लू, वायरल फीवर, इन्फेक्शन, मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां जैसी तमाम बीमारियां फैलने लगती हैं. इसलिए अन्य मौसम की तुलना में इस मौसम में खुद की सेहत पर अधिक ध्यान देना चाहिए. अब सवाल है कि आखिर प्रेग्नेंट महिलाएं बरसात में खुद का ख्याल कैसे रखें? किन बीमारियों का बढ़ता है जोखिम? शिशु की सेहत पर क्या होता है असर? इन सवालों के बारे में News18 को बता रही हैं संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योत्सना देवी-

प्रेग्नेंट महिलाएं बरसात में इन 5 तरह से खुद को रखें हेल्दी

हाइड्रेट रहें: डॉ. ज्योत्सना देवी बताती हैं कि, गर्भावस्था के दौरान आपका हाइड्रेट रहना बेहद जरूरी है. क्योंकि, बरसात के मौसम में नमी होने से प्यास कम लगने लगती है. इस स्थिति में शरीर में पानी की हो सकती है, जिससे यूरिन इन्फेक्शन समेत तमाम बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है. इतना ही नहीं, पानी की कमी होने से प्रसव में भी दिक्कत हो सकती है.

हल्की एक्सरसाइज करें: गर्भावस्था के दौरान एक्टिव रहना बेहद फायदेमंद है. इसके लिए आप घर पर ही हल्का व्यायाम कर सकती हैं. इस दौरान योग, स्ट्रेचिंग या एरोबिक एक्सरसाइज कर सकती हैं. ध्यान रहे कि, बाहर कम से कम ही निकलें.

हेल्दी डाइट लें: बरसात के मौसम में खाने वाली चीजों में बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ता है. ऐसे में कोशिश करें कि ताजा भोजन ही खाएं. बता दें कि, बासे भोजन पर बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करता है. इस तरह का भोजन करने से फ़ूड पॉइजनिंग या अन्य बीमारी का जोखिम बढ़ सकता है.

मच्छरों से बचाव: बरसात शुरू होते ही मच्छरों का कहर बढ़ जाता है. इसलिए खुद का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है. क्योंकि, मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया आदि का खतरा हो सकता है. इसका असर सिर्फ मां के स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है.

फिर से जी उठी ये पारंपरिक कला, इस सेंटर ने बदली कारीगरों की जिंदगी

आरामदायक कपड़े पहनें: डॉक्टर्स प्रेग्नेंसी में हमेशा आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह देते हैं. साथ ही पसीना या अन्य कारणों से गीले हुए कपड़े पहनने से बचें. क्योंकि, इस तरह की नमी से बैक्टीरिया पनप सकते हैं. जिससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।

बजट:2024, रोजी-रोटी और राजनीति का कॉकटेल

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2024-25 का वित्तीय बजट संसद में पेश कर दिया है। बजट में रोजी,रोटी, और रोजगार समेत बिहार और आन्ध्र प्रदेश की राजनीति के सुर भी छेड दिए है। इससे बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव ने विशेष राज्य के दर्जे पर मोदी सरकार समेत बिहार के मुख्य मंत्री से इस्तीफा देने तक की सलाह तक दे डाली। जबकि बिहार के लिए सडक, परिवहन, पर्यटन के लिए लाखों करोड रूपये बजट में शामिल है। जो बिहार के विकास में खर्च किए जाएगे। इनमें बाढ नियंत्रण के लिए 1500 करोड का प्रावधान किया गया है। बिहार में हाईवे निर्माण के लिए 26000 करोड, पर्यटन बढाने पर जोर के तहत कई धार्मिक स्थलों समेत नालंदा में पर्यटन का विकास, काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर का निर्माण, हिंदू बौध और जैन तीरथ स्थलों का निर्माण किया जाएगा। यह बिहार को दी गई विशेष तवज्जो से ध्यान हटाकर राजनीति के तहत नीतिश का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जबकि बजट में मुद्र लोन की

लिमिट को बढाकर 20 लाख करोडणरूपये कर दिया है। 50 मल्टी प्रोडेक्ट फूड यूनिट लगाए जाएगें। वहीं सरकार ने 109 फसलों पर अपना फोकस रखा है। राष्ट्रीय मार्किट फूड हॉट के लिए योजना पर कार्य किया जाएगा। ग्रामीण विकास पर 2.66 लाख करोड खर्च किए जाने का प्रावधान है।किसानों को अधिकतम एमएसपी दी जाएगी। युवाओ के लिए 2 लाख करोड रूपये रखे गए है। इससे 4.10 करोड युवाओ को फायदा होगा। युवाओ को एक महीने की सैलरी सरकार देगी। वहीं क्रेडिट गारंटी स्कीम का एलान किया गया है। अब 100 करोड रूपये तक का कर्ज ले सकेगे। सरकार ने ऐलान किया है कि सिडबी (SIDBI) के 25 नए ब्रांच खोले जाएगे। युवाओ को 6000 रूपये महीने का पेमेंट किया जाएगा।वहीं काम करने वालो के बच्चो के लिए NPS वात्सल्य योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा 25000 गांवो में पक्की सडक बनाने का लक्ष्य है। 11500 हजार करोड रूपये सिंचाई परियोजना के लिए खर्च किये जाएगें। वहीं अर्बन। हाउसिंग के लिए 10 लाख करोड रूपये इंवेस्टमेंट का प्रावधान किया गया है। वहीं 1 करोड घर सूर्य पर आधारित बिजली योजना की भी शुरूआत करने जा रही है। मोदी सरकार ने 2024-25 के लिए कुल बजट राशि 32 लाख करोड रूपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल के समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, आई पी सिंह को 2024 का पेश बजट रास नहीं आया है। उन्होने सोशल मिडिया X पर पोस्ट कर लिखा कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को 50000करोड रूपये की मदद ? दोनों सरकार के फीफा जी है। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश को विगत 10+1=11 साल में कुछ नहीं मिला ,सिवाय झुनझुना के । सपा नेता की यह प्रतिक्रिया अब चर्चा में बनी हुई है। बजट 2024: टैक्स पेयर्स के लिए बडा ऐलान।

टैक्स पेयर्स को बडी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टेंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढा दी है। इसे 50 हजार से बढाकर 75000 रूपये सालाना कर दिया है। यह बदलाव न्यू टैक्स रिजीम के तहत किया गया है। वहीं टैक्स स्लैब में भी बदलाव हुआ है।

अब 15 लाख सालाना की आय 30 फीसदी का टैक्स लागू होगा। न्यू टैक्स रिजीम के तहत नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अगर किसी की इंकम 7 लाख से ज्यादा होती है तो उसे 3 लाख सालाना इन्कम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।वहीं 3 से 7 लाख सालाना आय पर 5 प्रतिशत, 7 से ज्यादा और 10 लाख तक के सालाना इन्कम पर 10 प्रतिशत, 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक की सालाना इन्कम यर 15 प्रतिशत, 12 लाख से ज्यादा 15 लाख रूपये तक की आमदनी पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा सालाना आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम के तहत संशोधित टैक्स स्लैब :-

0.3 लाख पर 0 प्रतिशत टैक्स. 0.3 लाख से ज्यादा और 7 लाख पर 5 % टैक्स। 7 लाख से ज्यादा और 10 लाख पर 10 % टैक्स। 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख पर 15 % टैक्स। 12 लाख से ज्यादा 15 लाख पर 20 % टैक्स। 15 लाख से ज्यादा सालाना आय पर 30 % टैक्स। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार सालाना से बढाकर 75000 रूपये सालाना हो गया है। इसका मतलब है कि 7.75 लाख सालाना आय होने पर भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।

देशभर के ESIC अस्पतालों में नेशनल मेडिकल लैबोरेट्री प्रोफेशनल सप्ताह 17 से 23 जुलाई, संपन्न

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देशभर के तमाम ईएसआईसी अस्पतालों में नैशनल मेडिकल लैबोरेट्री प्रोफेशनल सप्ताह का आयोजन किया गया। इस बावत चिकित्सा प्रयोगशाला प्रोधोगिकीविद सुनील सरकनिया ने बताया कि देशभर के ईएसआईसी अस्पतालों में 17 से 23 जुलाई तक चले साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत फ्री मेडिकल चेक-अप कैंप, मरीजों और स्टाफ के बीच बिमारियों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम, सतत चिकित्सा शिक्षा के तहत विभिन्न विषयों पर लेक्चर, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, नेत्रदान संबंधी जागरूकता, जनरल हैल्थ अवेयरनेस के अलावा मरीजों के खान-पान से संबंधित लोगों को पर्चे वितरित किए गए। इसके अलावा वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत अस्पताल में छायादार पौधे लगाए गए। वहीं सेफ बायोमेडिकल डिस्पोजल की बावत प्रबंधकीय जागरूकता तथा अग्निशमन पर भी विस्तृत चर्चाए की गई। सुनील सरकनिया ने बताया कि सत्ताह भर चले इस सफल कार्यक्रम में सभी नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एवं समस्त प्रयोगशाला कर्मियों ने पूरे वीक में बढचढ कर सफलतापूर्वक शिरकत की और आयोजन को सफल बनाया। इस पूरे वीक के दौरान चिकित्सा प्रयोगशाला प्रायोगिक, श्रीमती इन्द्राणी कुमारी, किशोर केरकेट्टा, विनेश मेषराम की उपस्थित विशेषतौर पर सराहनीय रही।

कहीं सूखा कहीं बरसात बजट में बंदर बाट

सुषमा रानी

नई दिल्ली। बजट के घोषणा होते ही सभी पार्टियों में अपने-अपने नजरिए से बजट में कुछ अच्छा तो कुछ खामियां नजर आई बजट को लेकर के परमजीत सिंह पम्मा चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना है कि व्यापारियों को इस बजट से काफी उम्मीद थी के उनको कुछ राहत मिलेगी इतना टैक्स देने के बाद भी सरकार ने ना तो व्यापारियों के लिए कोई पैकेज की घोषणा की ना ही कोई छूट देने की बात की जबकि वित्त मंत्री ने खुद माना के जीएसटी व इनकम टैक्स भरपूर आ रहा है।

सरकार एक तरफ तो नौकरी और रोजगार देने की बात कर रही है दूसरी तरफ उद्योग व ट्रेडर्स बंद होने की कदर पर आ रहे हैं। बिजली, पेट्रोल, डीजल पर जीएसटी ज्यादा होने के कारण हमारा उद्योग बाहर से आने वाले देशों के समान का मुकाबला नहीं कर पा रहा है।

व्यापारी पूरी जिंदगी टैक्स इकट्ठा

कर सरकार के खजाने भरता है लेकिन उनकी सामाजिक सरक्षा का ध्यान नहीं दिया गया। बजट से निराशा हूई है। व्यापार जगत को लेकर इस बजट से काफी नाखुश है।

वही बजट से युवाओं और रोजगार को लेकर के वकार चौधरी पूर्व सांसद प्रत्याशी बसपा पूर्वी दिल्ली ने कहा कि मोदी सरकार 3 का बजट निराशाजनक रहा रोज़गार कैसे पैदा होगा और युवाओं के साथ धोखे वाला बजट पेश किया है ।

बसपा नेता वकार चौधरी ने आज पेश हुए बजट पर निराशा व्यक्त की है उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के साथ धोखा हुआ है , सिर्फ़ अपने सहयोगियो को रेवड़ी बाटी है ।शिक्षा आदि में भी बहुत कम बजट दिया है ।युवाओं को रोज़गार कैसे मिलेगा कैसे देश तरक्की करेगा अभाव दिखा कुल मिलकर इस बार का बजट एनडीए के सहयोगियों को खुश और आम जानता को निराश करने वाला बजट रहा।

बजट को लेकर एडवोकेट पारीजा, का कहना है कि नया बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। 3 लाख की आय वाले निम्न आय वर्ग को भी कर देना होगा। नई पीढ़ी के नौकरीपेशा और निम्न आय वर्ग को अगले साल से कर देना होगा। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और उन्हें वजीफा देने की बड़ी योजनाएं हैं। लेकिन यह हकीकत में बदल पाती है या नहीं, यह देखना होगा। हमेशा की तरह सबसे ज्यादा बजट रक्षा खर्च के लिए आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य, वाणिज्य और उद्योग तथा सामाजिक कल्याण के लिए कम बजट रखा गया है। 26% बजट ऋण और देनदारियों से आएगा, जिस पर हमें 19% ब्याज देना होगा !पेंशन के लिए सिर्फ 4% बजट आवंटित किया गया है !

कुल मिलाकर निम्न आय वर्ग, पेंशनभोगी और नई पीढ़ी इस बजट से प्रभावित होगी। इसमें बड़े-बड़े वादे किए गए हैं, जिन्हें पूरा करना मुश्किल होगा।

दिल्ली में केबल और इंटरनेट माफिया ने फैला रखा है मौत का जाल, यूपीएससी एस्पिरेंट से पहले भी गई हैं कई जानें

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के पटेल नगर इलाके में सोमवार को हुई वर्षा के बाद एक यूपीएससी छात्र की सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। दिल्ली में जगहों पर केबल व इंटरनेट माफिया ने तारों का जाल फैला रखा है जिससे जान जाने का खतरा रहता है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सरकारी लापरवाही और केबल व इंटरनेट माफिया ने युवक की जान ले ली। लेकिन, यह केवल दिल्ली के पटेल नगर का मामला नहीं हैं। अनधिकृत कॉलोनियों से लेकर नियमित कालोनियों में केबल टीबी और इंटरनेट माफिया का यह जाल फैला हुआ है।

मिलीभगत से लगे हैं बक्से

जहां बिजली विभाग से लेकर स्थानीय पुलिस के अधिकारियों से मिलीभगत करते बिजली के खंभों पर केबल टीबी और इंटरनेट के बक्से लगे हुए हैं, जिनमें करंट आने से भी जान का खतरा रहता है। नई दिल्ली-पटेल नगर के 8 ब्लाक में इसी घटनास्थल पर बिजली का करंट लगने से छात्र की मौत हो गई।

छत से जमीन की जगह दिखते हैं सिर्फ तार

केबल टीबी के लिए लगे बक्से और प्राइवेट इंटरनेट

के बक्सों से तारों का जाल इस तरह से फैला हुआ है कि गलियों में घरों की छत से तार ज्यादा और जमीन कम नजर आती है। इसके पीछे प्राइवेट केबल टीबी और इंटरनेट माफिया का हाथ होता है। जो बिना इजाजत के बिजली व पुलिस अधिकारियों की मदद से इस काम को अंजाम देते हैं। नामी इंटरनेट कंपनियों से यह माफिया कम दाम में सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिससे लोग ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। इससे तारों का जाल इलाके में फैल जाता है।

अवैध रूप से डाले जा रहे तार

दिल्ली में खंभों पर इंटरनेट व केबल के तारों को अवैध रूप से डाला जा रहा है। गलियों व कालोनियों में लगे खंभों पर इन अवैध तारों के डालने से वर्षा के दौरान हादसे का खतरा मंडराता रहता है। ऐसी ही घटना पटेल नगर में सोमवार को घटित हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक यूपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी नीलेश को अपनी जान गंवानी पड़ी।

अधिकारी नहीं करते कार्रवाई

पटेल नगर की लगभग सभी कॉलोनियों में खंभों पर तारों का गुच्छा बना हुआ है। विद्युत विभाग और इंटरनेट व केबल प्रदाताओं की लापरवाही से लोगों की जान जा रही है, लेकिन संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पटेल नगर में जहां घटना हुई है वहां पर भी यही देखने को मिला है। यहां पर केबल टीबी और इंटरनेट के कुछ तार तो टूटकर जमीन पर गिरे हुए हैं।

जलभराव से करंट का खतरा

इससे जलभराव में करंट फैलने का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से इस समस्या को लेकर शिकायत कर चुके हैं मगर समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। घटनास्थल के पास रहने वाले अजविंदर सिंह ने बताया कि वह कई बार प्रशासन ने अवैध तारों व सड़कों पर जलभराव को लेकर शिकायत कर चुके हैं मगर अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। शायद वह किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। वहीं, अन्य चंदा ने बताया कि गली में वर्षा के बाद जलभराव होता है, जिससे परेशानी होती है मगर जलभराव की समस्या की शिकायत करते-करते थक गए हैं। हमारी कोई नहीं सुनता।

एनसीआर में बरसात में सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण विगत दो वर्षों में हुए हादसे

25 जून 2023 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महिला की मौत करंट लगने की वजह से हो गई।

27 जून 2023 को तैमूर नगर में कॉलोनी में जलभराव होने से करंट की चपेट में 17 वर्षीय युवक आ गया और उसकी मौत हो गई।

2 जुलाई 2023 को एलएन अस्पताल में निर्माणधीन इमारत में करंट आने से एक श्रमिक की मृत्यु हो गई।

19 मई 2024 को किराडी के इंद्रा एन्क्लेव से गुजरते हुए एक खुले तार से रेहड़ी में करंट आ गया, जिससे व्यक्ति की मौत गई।

29 जून 2024 सिरसपुर अंडरपास में जलभराव के दौरान करंट आ गया और दो बच्चों की मौत हो गई।

28 जून 2024 को किराड़ी में एक दुकान के बाहर लगे लोहे के पाइप में करंट आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।

13 जुलाई 2024 को यमुना विहार इलाके में बिजली के खंभे में करंट आने से महिला की मौत।

सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के दो पुलिसकर्मियों को थाने से किया गिरफ्तार, एक एसआई तो दूसरा है एएसआई

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली पुलिस के कई पुलिसकर्मी पिछले कुछ दिनों में भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार हो चुके हैं। हाल ही में सीबीआई ने एक थाने के एसआई और एएसआई को गिरफ्तार किया है। दोनों मुकदमा दर्ज करने के लिए रिश्वत ले रहे थे। सीबीआई ने इन्हें थाने से गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते भी पांच पुलिसकर्मी रिश्वत को लेकर गिरफ्तार हुए थे।

नईदिल्ली। दिल्ली पुलिस में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा रिश्वत मांगने से आजिज आकर आए दिन लोग उनके खिलाफ सीबीआई में शिकायत कर रहे हैं, जिससे सीबीआई थानों व यूनिटों में छापा मार पुलिसकर्मियों को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर रही है। ताजा मामला मंगलवार को दक्षिण-पूर्वी जिले के सरिता विहार थाने का सामने आया है। सुबह छह बजे सीबीआई ने सरिता विहार थाने में छापा मार एसआई राज कुमार व एएसआई रघुराज को 35 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।

मुकदमा रद्द करने को ली रिश्वत

आरोपी दोनों पुलिसकर्मियों ने दहेज प्रताड़ना के मामले में दर्ज मुकदमे को रद्द करने के एवज में रिश्वत ली थी। दोनों पुलिसकर्मी कई सालों से सरिता विहार थाने में तैनात थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग ने दोनों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। इस मामले ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस की छवि धूमिल कर दी है।

रिश्वत मांगने की शिकायत की

सीबीआई का कहना है कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने शिकायत कर आरोप लगाया कि पिछले साल सरिता विहार थाने में उनके खिलाफ दर्ज दहेज प्रताड़ना के मामले में केस को रद्द करने के एवज में एसआई और एएसआई ने उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। सीबीआई ने पहले दोनों पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबरों को ट्रेकिंग पर लगाकर उनकी शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया। साक्ष्य मिल जाने के बाद सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया।

थाने में जाकर दी रिश्वत

सीबीआई के निर्देश पर शिकायतकर्ता ने मंगलवार सुबह दोनों पुलिसकर्मियों को पैसे देने थाने गया। जैसे ही उसने पुलिसकर्मियों को पैसे दिए सीबीआई की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। सरिता विहार थाने में दोनों पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की डीडी एंट्री करा दी गई।

युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए करियर काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन

सुषमा रानी

दिल्ली, शमां एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसायटी ने सोफिया पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मेन रोड बृजपुरी पर 12वीं क्लास पढ़ने के बाद घर बैठे लड़के - लड़कियों को पैरामेडीकल और नॉन मैडिकल के फुल टर्म व शॉर्ट टर्म कॉर्स की पूर्ण जानकारी दी।

शमां संस्था के महासचिव डॉक्टर फहीम बेग ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आज आप सबको यहां बुलाकर हम रोज़गार से जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं जिसमें हमारी संस्था द्वारा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, सर्वेयर, डिजिटल मार्केटिंग आदि के बारे में जानकारी देकर आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं इसके अतिरिक्त आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट मेकिंग , आधार कार्ड, पहचान पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट और अन्य सरकारी दस्तावेज़ बनाने की पूर्ण जानकारी भी दी जा रही है जिस से आप जीवन भर लाभ उठाते रहेंगे।

SPMI के सेंटर हेड जमील सैफी ने युवाओं को जानकारी देते हुए बताया कि साइंस और नॉन साइंस के

छात्रों के लिए सोफिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में डीएमएलटी, ऑपरेशन थियेटर टेक्निशियन , x-ray टेक्निशियन, डायलिसिस टेक्निशियन, इमरजेंसी सर्विसिस टेक्निशियन आदि कराए जाते हैं जिनकी फीस आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए बेहद कम रखी है इन कोर्सेज के पूरा होने पर हम कामयाब उम्मीदवारों 100% रोज़गार से जोड़ने का जिम्मेदारी लेते हैं।

सोफिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सुहैल सैफी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम अपने सेंटर में डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप , सिलाई, कढ़ाई आदि शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए जाते हैं जो मुफ्त होते हैं। इसके अलावा कोई बच्चा सिर्फ 10वीं पास है तो उसके लिए भी सर्वेयर की जॉब है जिससे वो तुरंत आमदनी से जुड़ सकता है। सैफी ने शमां एनजीओ की टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का यहां आना और उनको रोज़गार से जोड़ने का यह प्रयास सराहनीय है इसके लिए डॉक्टर फहीम बेग बधाई के पात्र हैं। शिफा मिर्ज़ा ने डिजिलॉकर एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से बताया। इस वर्कशॉप में अमरीन खान, रविकांत मिश्रा, रिचा आदि ने भी 100 से अधिक प्रतिभागी युवाओं का मार्गदर्शन किया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित किया

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने आज बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए अब ज्यादा समय नही है, हमें केन्द्र में भाजपा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की जनविरोधी नीतियों, जनता की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति उदासनीता, भ्रष्टाचार के साथ बिजली कटौती, जल संकट, बढ़े हुए बिल, जल भराव, सड़कों की बदहाली, जल निकासी में विफल नालों सहित जल और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं को हर घर तक पहुँचाना होगा। जिला कार्यकारणी बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष चौ0 जुबेर अहमद ने सीमापुरी विधानसभा में ताहिरपुर क्षेत्र में किया।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के साथ कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक चौ0 मतीन अहमद, वीर सिंह धींगान, भीष्म शर्मा, आर्ब्जवर अशोक जैन, जितेन्द्र बघेल, कैलाश जैन, निगम पार्षद मौहम्मद जरीफ, पूर्व पार्षद चौ0 अजीत सिंह, सेवादल मुख्य संगठक सुनील कुमार, राजकुमार जैन सभी ब्लाक अध्यक्ष, जिला, ब्लाक, अग्रिम

संगठन, सेल एवं विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि हमें बाबरपुर जिला की 2-3 विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित वोट मिला, परंतु सभी जिला कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अपनी सभी विधानसभाओं में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस जल्द ही संगठन को और मजबूत बनाने के लिए 258 ब्लाक कांग्रेस कमेटियां की प्रस्तावना पर मौहर लगाकर प्रत्येक ब्लाक को दो मंडल में विभाजित करने की घोषणा कर देगी। मंडल बनाने के साथ-साथ मंडलों को सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया भी चल रही है जिसमें 5-7 बूथ का एक सेक्टर बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से एक महीना पूर्व दिल्ली कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता दिल्ली के प्रत्येक बूथ पर मतदाता के नजरिए को जानने का काम पूरा कर लेगा। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के विश्वास में बढ़ोत्तरी दर्ज करके कांग्रेस कार्यकर्ता गरीब, मध्यम वर्ग, पिछड़ा, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग, मजदूर, रेहड़ी पटरी, खोमचा वाले, युवा और महिलाऐं सहित सामाजिक, धार्मिक संगठनों व एनजीओं से जुड़े लोगों से सम्पर्क साधकर कांग्रेस की विचारधारा और हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा देश के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत भी कराऐंगे।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से रिकॉड तोड़ बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई के कारण लगभग समाज के हर वर्ग प्रभावित है चाहे नौकरीपेशा, वकील, डाक्टर, मजदूर, ऑटो चालक, ड्राईवर, दुकानदार या छोटा मोटा कारोबार करने वाला हो। सभी पेट्रोल डीजल, सीएनजी की दरों के कारण दोहरी मार झेल रहे है और दिल्ली सरकार हर वर्ष बिजली उपभोक्ताओं पर पीपीएसी की दरों में 8-10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके लगातार आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी दिल्ली में अपनी एकजुटता को कायम करके भाजपा और आम आदमी पार्टी की मिली भगत और नूरा कुश्ती के खेल को दिल्लीवालों के

कैसे निकलेगा सफाई कर्मचारियों की समस्या का हल, हड़ताल से शहरवासियों को होती है परेशानी

नोएडा में सफाई कर्मचारी आए दिन हड़ताल पर चले जाते हैं इससे शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ जाती है। इससे शहरवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब सफाईकर्मियों की समस्या का हल निगमों व प्राधिकरणों के अध्ययन से निकाला जाएगा। सीईओ के आदेश पर प्राधिकरण जनस्वास्थ्य विभाग ने वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी बनाई है।

नोएडा। आए दिन नोएडा में साफ-सफाई कर्मचारी छोटी छोटी मांगों को लेकर प्राधिकरण अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल पर चले जाते है। इससे शहरवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

हड़ताल पर जाने की वजह से शहर की साफ-सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है, जिससे निपटने में प्राधिकरण जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारी काफी मशक्कत करनी पड़ती, उसके बाद व्यवस्था को सुचारू कराया जाता है। ऐसे में साफ-सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का स्थाई समाधान और शहर में साफ-सफाई व्यवस्था को निर्बाध कराने की दिशा में प्राधिकरण का जन स्वास्थ्य विभाग कदम बढ़ा चुका है।

हड़ताल का निकाले स्थाई समाधान

प्रतिदिन हड़ताल से आजिज आए प्राधिकरण सीईओ डॉ लोकेश एम ने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का स्थाई तलाशने के विकल्पों पर काम किया जाए। जिससे कर्मचारियों के वेतन विसंगति का स्थाई हल निकाल सके। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों से कहा है कि वह एक कमेटी बनाकर एनसीआर समेत आसपास के सभी नगर निगमों और प्राधिकरणों का गहनता से अध्ययन करे। पता लगाए कि किस नगर निगम या प्राधिकरण में सबसे अधिक कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, उसका प्रारूप क्या है।

नोएडा प्राधिकरण से अन्य की ओर से दिए जाने वाले वेतन से कितनी भिन्नता है। वेतन दिए जाने का तरीका क्या है, व्यवस्था को प्राधिकरण में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है इससे आए दिन प्राधिकरण जन स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारी वेतन विसंगति को लेकर सड़क पर उतरे और न ही हड़ताल कर जनता को प्रताड़ित करे।

कमेटी का किया गया गठन

सीईओ के आदेश पर जन स्वास्थ्य की ओर से वित्त नियंत्रक स्वतंत्र कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक (जल) आरपी सिंह, उप महाप्रबंधक (सिविल) विजय कुमार रावल, सदस्य सचिव गौरव बंसल की कमेटी गठित कर दी है। जो एनसीआर समेत अन्य जगहों के नगर निगमों व प्राधिकरणों में साफ-सफाई कर्मचारियों के वेतन व सुविधाओं को लेकर अध्ययन करेगी। अध्ययन रिपोर्ट को सीईओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, इसके बाद अक्टूबर आयोजित होने वाली प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कर्मचारियों की समस्या हल के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा, अनुमोदन के बाद वेतन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

चुनाव परिणाम घोषित हुए बगैर सचिव की कुर्सी पर बैठे हरेंद्र गौतम, विरोध में जमकर हंगामा; दोनों पक्षों के बीच

परिवहन विशेष न्यूज

चुनाव परिणाम घोषित हुए बिना बार सचिव की कुर्सी पर बैठना हरेंद्र गौतम को भारी पड़ गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे प्रत्याशी अमित के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों में तीखी बहस हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। पढ़िए हरेंद्र गौतम सचिव की कुर्सी पर क्यों बैठे और विरोध में मारपीट क्यों हुई?

गाजियाबाद। बार एसोसिएशन के सचिव पद का चुनाव परिणाम घोषित हुए बगैर सोमवार को हरेंद्र गौतम बार सभागार में सचिव की कुर्सी पर बैठ गए।

समर्थकों ने जमकर हंगामा किया

सूचना पाकर सचिव पद के प्रत्याशी अमित नेहरा के समर्थक मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। दोनों पक्षों के बीच जमकर तकरार व मारपीट हुई। इसके बाद रूम को बंद कर दिया गया और हरेंद्र गौतम व अमित नेहरा दोनों पक्षों के लोग बार सभागार के बाहर धरने पर बैठ गए।

वहीं, चुनाव परिणाम घोषित हुए बिना सचिव की कुर्सी पर बैठने का संज्ञान लेकर चुनाव संयोजक स्नेह त्यागी ने हरेंद्र गौतम को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। उन्होंने नोटिस में पूछा कि क्यों न आपकी प्राथमिक सदस्यता को अविलंब निरस्त किया जाए?

हरेंद्र गौतम को सचिव घोषित किया गया

दरअसल, सोमवार सुबह कार्यवाहक अध्यक्ष व मुख्य चुनाव अधिकारी मृदुला त्यागी राय का एक पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके माध्यम से उनके द्वारा हरेंद्र गौतम को सचिव घोषित किया गया। इसका नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। इसी के बाद हरेंद्र गौतम बार सभागार में पहुंच कर सचिव की कुर्सी पर बैठ गए।

उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और स्वयं को सचिव बताते हुए प्रस्ताव भी जारी कर दिया। इसी के बाद मौके पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। आरोप लगाया गया कि सचिव की सीट के पास लगी आंबेडकर की तस्वीर को गिरा दिया गया।

पूर्व सचिव व चुनाव संयोजक स्नेह त्यागी ने कहा कि अभी चुनाव कमेटी ने सचिव के पद का परिणाम की घोषणा नहीं किया है। कार्यकारी अध्यक्ष की तरफ से सचिव पद के परिणाम से संबंधित घोषणा पूरी तरह अंवैधानिक है, जिसे तत्काल खारिज किया गया।

सचिव पद के लिए 25 जुलाई को होगा मतदान

उन्होंने कहा कि सचिव पद के लिए मतदान 25 जुलाई को सुबह आठ बजे से होगा। इसके बाद उसी दिन मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर उन्होंने मतदान के दिन अतिरिक्त फोर्स के साथ पीएसी तैनात करने की मांग की गई है।

यह है पूरा मामला

19 जुलाई को बार चुनाव की मतगणना में सचिव पद पर तीन प्रत्याशियों को मिले मतों की घोषणा की गई, मगर किसी को विजयी घोषित नहीं किया गया था। सचिव पद पर हरेंद्र गौतम को 892, अमित नेहरा को 891 वोट मिले थे जबकि, वरुण त्यागी को 754 वोट। 18 वोट निरस्त घोषित किए गए थे। कुल वोट 2,553 पड़े थे लेकिन, सचिव पद पर 2,555 वोट की गिनती हुई। दो बैलेट पेपर अतिरिक्त मिले।

वहीं, इसी कारण कमेटी ने सचिव पद का परिणाम घोषित नहीं किया था। विरोध में हरेंद्र गौतम बार सभागार के बाहर धरने पर बैठ गए थे। वह दोबारा मतदान का विरोध कर रहे हैं जबकि, अमित नेहरा व उनके समर्थक दोबारा मतदान की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर विवाद है।

इसी बीच नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष दीपक शर्मा ने सचिव पद का चुनाव परिणाम घोषित न होने तक सह-सचिव प्रशासन को प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का अधिकार कार्यकारिणी की बैठक के बाद दिया।

क्या है सेप्टीसीमिया? इस बीमारी से लड़के की हुई मौत

मां और बहन बोली- सो रहा है, पास में कई दिनों तक रखा शव

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद में एक किशोर की मौत हो गई। उसकी सेप्टीसीमिया नाम की बीमारी से जान गई थी। घर में किशोर की मां और बहन थी। दोनों ने शव को अपने पास कई दिनों तक रखा। इसकी जानकारी तब हुई जब पड़ोसियों को दुर्गंध आने लगी थी। उन्होंने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी फिर शव को बाहर निकाला गया।

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक लड़के की मौत हो गई। लड़के की मां और उसकी बहन उसके शव को कई दिनों तक अपने पास रखे रहीं। उनको लगा कि वह सो रहा है। पुलिस ने मंगलवार को इसके बारे में जानकारी दी। मामला तब सामने आया, जब पड़ोसियों को फ्लैट से दुर्गंध आने लगी। उन्होंनने रविवार को पुलिस से शिकायत दी।

पुलिस के अनुसार, लड़के की सेप्टीसीमिया नाम की बीमारी से मौत हुई है। तेजस जैन (13) अपनी मां कोमल जैन (50) और बहन काव्या (22) के साथ गाजियाबाद की चंद्रनगर कॉलोनी में एक फ्लैट में रह रहा था। मां और बहन मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं।

पति की एक दशक पहले मौत हुई

कोमल के पति की एक दशक पहले मौत हो गई थी। उसी के बाद से मां और बेटी मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही थीं।

जब फ्लैट पर पहुंची पुलिस

साहिबाबाद के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ा। तेजस का शव फर्श पर पड़ा था। वहीं, कोमल और काव्या उसके पास बैठी थीं। दोनों ने बताया कि तेजस सो रहा है।

किसी से बात नहीं करता था परिवार

एसीपी के अनुसार, पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि परिवार हमेशा लाइट बंद रखता था और कॉलोनी में किसी से बात नहीं करता था। बीमारी के कारण काव्या को 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कोमल का भाई प्रशांत जैन उनका खर्च उठा रहा था। वह दिल्ली के चावड़ी बाजार में रहता था।

उन्होंने कहा कि पुलिस को घर गंदी हालत में मिला और कोमल और काव्या भी दयनीय हालत में थे। मंगलवार को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि तेजस की मौत सेप्टीसीमिया से हुई है। एसीपी ने कहा कि उसका अंतिम संस्कार बुधवार को किया जाएगा।

क्या होता है सेप्टीसीमिया

यह एक प्रकार का रक्त का संक्रमण है जो बच्चे के जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसके कारण शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। बच्चों के अलावा सेप्टीसीमिया बड़ों को भी हो सकता है। इस दौरान बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कमजोर इम्यून तंत्र होने पर यह ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सेप्टीसीमिया के चलते शरीर के अंग फेल तक हो जाते हैं और मृत्यु तक हो सकती है।

लक्षण मिलने पर समय से ही उपचार कराकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही नवजात के परिवारीजन को चाहिए कि जन्म के साथ ही बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखें। जन्म के साथ यदि बच्चा न रोये या फिर देर से रोये, दूध न ले या फिर ले तो कम, बहुत रोने लगे तो उसे तुरंत डाक्टर के पास ले जाना चाहिए। वहीं आंतों में संक्रमण से सेप्टीसीमिया का खतरा बन रहता है।

211 तालाबों पर अवैध कब्जा कर बने मकान हटाएं जाएंगे, टीमें गठित; प्रशासन ने NGT को सौंपी रिपोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा प्रशासन की ओर से प्रस्तुत की गई 120 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार तीनों तहसील जेवर सदर और दादरी में स्थित तालाबों में से 211 तालाबों पर भूमाफिया की ओर से अतिक्रमण किया गया है। इन अतिक्रमण के खिलाफ 804 मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकांश तालाबों में बेदखली के आदेश पारित हो चुके हैं। दादरी में सबसे अधिक 480 तालाब हैं जिनमें से 134 पर अतिक्रमण है।

ग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन की नजर से अब भूमाफिया बच नहीं पाएंगे। तालाबों पर कब्जा कर बनाई गई अवैध इमारतों को हटाने की कार्रवाई में तेजी कर दी गई है। एनजीटी को जिलाधिकारी की ओर से सौंपी रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है कि जिले में 1018 में से 211 तालाब गायब हो चुके हैं। यह रिपोर्ट अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में प्रस्तुत की गई है।

प्रशासन की ओर से प्रस्तुत की गई 120 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार तीनों तहसील जेवर, सदर और दादरी में स्थित तालाबों में से 211 तालाबों पर भूमाफिया की ओर से अतिक्रमण किया गया है। इन अतिक्रमण के खिलाफ 804 मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकांश तालाबों में बेदखली के आदेश पारित हो चुके हैं। दादरी में सबसे अधिक 480 तालाब हैं, जिनमें से 134 पर अतिक्रमण है। यहां 283 मामले दर्ज हुए। 249 में 3.6956 हेक्टेयर भूमि की बेदखली के आदेश पारित हुए है।

कार्रवाई के लिए कई टीमें गठित

जेवर तहसील में 293 तालाबों में से 29 पर अतिक्रमण है। यहां 168 मामलों में बेदखली के आदेश दिए गए हैं, जिनमें 2.8163 हेक्टेयर भूमि शामिल है। सदर तहसील में 245 तालाबों में से 48 अतिक्रमण हैं, जहां 353 मामलों में 5.4139 हेक्टेयर भूमि की बेदखली के आदेश हुए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व, पुलिस, प्राधिकरण और विकास विभाग की टीमें गठित की गई हैं। कई स्थानों पर निवासियों के मकान बने होने के कारण कार्रवाई में चुनौतियां आ रही हैं।

वैकल्पिक आवास व्यवस्था के बाद ही हटाया जाएगा

गरीब लोगों के लिए वैकल्पिक आवास व्यवस्था के बाद ही उन्हें हटाया जाएगा। कई जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सदर तहसील में भी पांच गांवों, जेवर में तीन गांवों में कार्रवाई हुई है। पूरी कार्रवाई के लिए आठ महीने का समय मांगा गया है। जेवर बांगर में गाटा संख्या 1955, 1956 में तालाब का सुंदरीकरण किया है। आलमपुर उर्फ लौदोना में गाटा संख्या 309 व 311 की सूरत बदली गई है। रबूपुरा में तालाब से अतिक्रमण हटाया है।

महानगरों में बढ़ता जानलेवा प्रदूषण गंभीर चुनौती

ललित गर्ग

केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण एवं हवा में घुलते जहरीले तत्वों की चुनौती के मुकाबले के लिये राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की घोषणा 2019 में की थी। जिसका मकसद था कि खराब हवा के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को कम किया जा सके।

चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी चर्चित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका लासेंट के हाल के अध्ययन में वायु प्रदूषण की बढ़ती विनाशकारी स्थितियों के आंकड़े न केवल चौंकाने वाले है बल्कि अत्यंत चिन्तातनक है। भारत के दस बड़े शहरों में हर दिन होने वाली मौतों में सात फीसदी से अधिक का मुख्य कारण हवा में व्याप्त प्रदूषण है। वहीं दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा साढ़े ग्यारह प्रतिशत है। भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण के रूप में पसर रही मौत के लिये सरकार एवं उनसे संबंधित एजेंसियों की लापरवाही एवं कोताही शर्मनाक है, क्योंकि सरकार द्वारा 131 शहरों को आवंटित धनराशि का महज 60 फीसदी ही खर्च किया जाता है। गंभीर से गंभीरतर होती वायु प्रदूषण की स्थितियों के बावजूद समस्या के समाधान में कोताही चिन्ता में डाल रही है एवं आम जनजीवन के स्वास्थ्य को चौपट कर रही है। महानगरों में प्रदूषण का ऐसा विकराल जाल है जिसमें मनुष्य सहित सारे जीव-जंतु फंसकर छटपटा रहे हैं, जीवन सांसों पर छाये संकट से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण एवं हवा में घुलते जहरीले तत्वों की चुनौती के मुकाबले के लिये राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की घोषणा 2019 में की थी। जिसका मकसद था कि खराब हवा के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार की कोशिश थी कि देश के चुनिंदा एक सौ तीस शहरों में वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2024 तक घातक धूल कणों की उपस्थिति को बीस से तीस फीसदी कम किया जा सके। लेकिन विडम्बना है कि तय लक्ष्य हासिल नहीं हो सके। महानगरों-नगरों को रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हालांकि लोगों को सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है, एंटीडस्ट अभियान को निरन्तर जीवन का हिस्सा बनाना होगा। लोगों को खुद भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी। लोगों को खुली जगह में कूड़ा नहीं फैंकना चाहिए और न ही उसे जलाया जाए। वाहनों का प्रदूषण लेवल चैक करना चाहिए। कोशिश करें कि हम निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली पटाखे जलाने की भौतिकतावादी मानसिकता को विराम देना जरूरी है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की वैश्विक अभिधारणा को मूर्त रूप देने के लिये इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की दिशा में गत दो-तीन साल में कई पायदान हम ऊपर चढ़े हैं, एक सकारात्मक वातावरण बना। लेकिन पटाखों से ज्यादा खतरनाक हैं पराली का प्रदूषण। पराली आज एक राजनीतिक प्रदूषण बन चुका है। दिल्ली एवं पंजाब में एक ही दल ही सरकारें है, दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार समाधान देती। प्रदूषण से ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा-सा दीपक गहन अंधेरे से लड़ता है। छोटी औकात, पर अंधेरे को पास नहीं आने देता। क्षण-क्षण अग्नि-परीक्षा देता है। पर हां! अग्नि परीक्षा से कोई अपने शरीर पर फूस लपेट कर नहीं निकल सकता। इसके लिये शहरों में वृक्षारोपण करके हरियाली का दायरा बढ़ाना, कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, इलेक्ट्रानिक वाहनों को प्रोत्साहन तथा इन वाहनों के लिये चार्जिंग स्टेशन बनाने जैसे प्रयास करने के सुझावों का क्रियान्वित करने की अपेक्षा है, इसके लिये जो कार्यक्रम प्रदूषण से ग्रस्त चुनिंदा शहरों में चलाया जाना था, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। जिससे समस्या उग्र से उग्रतर होती जा रही है। इसी कारण देश के अधिकांश शहर गंभीर वायु प्रदूषण

की चपेट में हैं। लेकिन स्थानीय निकायों व प्रशासन ने संकट की गंभीरता को नहीं समझा। इस दिशा में अपेक्षित सक्रियता नजर नहीं आई। प्रश्न है कि पिछले कुछ सालों से लगातार इस महासंकट से जूझ रहे महानगरों को कोई समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती? सरकारें एवं राजनेता एक दूसरे पर जिम्मेदारी ठहराने की बजाय समाधान के लिये तत्पर क्यों नहीं होते? प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रही है?

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये सक्रिय है, केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये करीब साढ़े दस हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। लेकिन विडम्बना है कि पर्याप्त फण्ड होने के बावजूद सिर्फ साठ फीसदी राशि ही इस मकसद के लिये खर्च की गई। वहीं सत्ताईस शहरों ने बजट का तीस फीसदी ही खर्च किया। कुछ शहरों ने तो इस मकसद के लिये आवंटित धन का बिल्कुल उपयोग नहीं किया। कैसे समस्या से मुक्ति मिलेगी? जीवाश्म ईंधन के उपयोग, सड़कों पर निरंतर बढ़ते पेट्रोल-डीजल वाहन, सार्वजनिक यातायात की बदहाली व कचरे का ठीक से निस्तारण न होने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लक्ष्य हासिल करना जटिल होता जा रहा है। अब समस्या की विकरालता को देखते हुए केंद्र सरकार इस दिशा में नये सिरे से गंभीरता से पहल कर रही है, जिससे प्रदूषित शहरों को दी जाने वाली राशि का यथा समय अधिकतम उपयोग हो सके। पराली की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1347 करोड़ रुपये और उपकरण दिए गए। अगर इस पर राजनीति करने की जगह ईमानदारी से काम होता तो प्रदूषण को कम करने की दिशा में हम कुछ कदम बढ़े होते।

वायु प्रदूषण एक जाना-पहचाना पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरा है। हम जानते हैं कि हम क्या देख रहे हैं जब भूरे रंग की धुंध शहर के ऊपर छा जाती है, व्यस्त राजमार्ग पर धुआँ निकलता है या धुएँ के ढेर से धुआँ निकलता है। वायु प्रदूषण मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों स्रोतों से उत्पन्न खतरनाक पदार्थों का मिश्रण है। वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, घरों को वातानुकूलित करने के लिए ईंधन तेल और प्राकृतिक गैस, एसी का उपयोग, विनिर्माण और बिजली उत्पादन के उप-उत्पाद, विशेष रूप से कोयला-ईंधन वाले बिजली संयंत्र, और रासायनिक उत्पादन से निकलने वाले धुएं मानव निर्मित वायु प्रदूषण के प्राथमिक स्रोत हैं। बढ़ता प्रदूषण वैश्विक स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक बड़ा खतरा है। वायु प्रदूषण सभी रूपों में, हर साल दुनिया भर में 6.5 मिलियन से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है यह संख्या पिछले दो दशकों में बढ़ी है। भारत के महानगरों में यह अधिक विकराल होती जा रही है। उच्च वायु प्रदूषण से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में कैंसर, हृदय रोग, श्वसन रोग, मधुमेह, मोटापा, तथा प्रजनन, तंत्रिका संबंधी और प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी विकार शामिल हैं। वायु प्रदूषण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक होने लगती है। महानगरों की हवा में उच्च सांद्रता है, जो बच्चों को सांस की बीमारी और हृदय रोगों की तरफ धकेल रही है। शोध एवं अध्ययन में यह भी पाया गया है कि दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले 75.4 फीसदी बच्चों को घुटन महसूस होती है। 24.2 फीसदी बच्चों की आंखों में खुजली की शिकायत होती है। सर्दियों में बच्चों को खांसी की शिकायत भी होती है। बुजुर्गों का स्वास्थ्य तो बहुत ज्यादा प्रभावित होता ही है। हवा में कैडमियम और आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कैंसर, गुर्दे की समस्या और उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। 300 से अधिक एक्यूआई वाले शहरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी सहित अनेक महानगर क्षेत्र में रहने वाले सांस के रूप में जहर खींचने को क्यों विवश है, इसके कारणों पर इतनी बार चर्चा हो चुकी है कि उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं। निस्संदेह, राज्यों के शासन व स्थानीय प्रशासन के वायु प्रदूषण को लेकर उदासीन रवैये से नागरिकों के जीवन का संकट बरकरार है। सर्वविदित तथ्य है कि न तो सरकारों के पास पर्याप्त संसाधन हैं और न ही ऐसा विशिष्ट कार्यबल। नागरिकों की जागरूकता व जवाबदेही बढ़ाकर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस विषम एवं ज्वलंत समस्या से मुक्ति के लिये प्रशासन एवं सरकारों को संवेदनशील एवं अन्तर्दृष्टि-सम्पन्न बनना होगा।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

हीरो सर्ज ईवी को मिला प्लेटिनम ए डिजाइन का अवॉर्ड

परिवहन विशेष न्यूज

दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को हीरो सर्ज ईवी के लिए प्रतिष्ठित 'प्लेटिनम ए' डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

हीरो सर्ज ईवी एक ऐसी गाड़ी है, जो महज 3 मिनट में स्कूटर से 3-व्हीलर बन जाता है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सर्ज ईवी को ऐसे डिजाइन किया है कि यह स्कूटर के रूप में इस्तेमाल में आ सकती है और जरूरत पड़ने पर इसे तिपहिया वाहन की शक्ल देकर इससे बिजनेस भी किया जा सकता है।

हीरो सर्ज ईवी को वाहन, मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन श्रेणी में प्रतिष्ठित 'प्लेटिनम ए' डिज़ाइन अवार्ड मिला है। सर्ज ईवी में सिर्फ़ 3 मिनट में दोपहिया वाहन से तिपहिया वाहन में बदलने की अनूठी क्षमता है। वाहन मोड स्विचिंग में अग्रणी, सर्ज ईवी में एक बुद्धिमान उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस है जो वाहन के प्रकार के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित होता है। उपयोगकर्ता केवल 3 बटन का उपयोग करके आसानी से मोड के बीच स्विच कर सकते हैं।

यह काम हीरो मोटोकॉर्प के इन-हाउस इनक्यूबेशन सेंटर 'हीरो हैच' में किया गया, जिसे कंपनी के भीतर इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। हीरो हैच टीम में कंपनी के मौजूदा टैलेंट शामिल हैं जो स्टार्ट-अप स्पिरिट के साथ काम करते हैं और कंपनी के संसाधनों का लाभ उठाते हैं। हीरो सर्ज एस32 ईवी जब भी भविष्य में लॉन्च होगी, तो यह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अपनी क्षमता और डिजाइन के लिए देश और दुनिया में अपना बड़ा नाम बना सकती है।

बजट 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, भारत सरकार का मेक-इन-इंडिया ईवी पर फोकस

परिवहन विशेष न्यूज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऑटोमोबाइल उद्योग का ज़िक्र नहीं किया। वित्त मंत्री ने फेम-3 का भी कहीं ज़िक्र नहीं किया। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के स्थानीयकरण पर काफ़ी ज़ोर दे रही है और इसके लिए सरकार ने कदम भी उठाए हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के स्थानीयकरण के लिए सरकार ने लिथियम, कॉपर और कोबाल्ट पर सीमा शुल्क घटा दिया है। इससे देश में लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण को और बढ़ावा मिलेगा। लिथियम और कोबाल्ट लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। इन तत्वों पर सीमा शुल्क में कमी से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को सही दिशा मिलेगी।

इस बजट 2024-25 में देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने, इन वाहनों का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करने के लिए ऑटो उद्योग के लिए लाए गए कुल बजट का लगभग आधा हिस्सा यानी 2,671 करोड़ रुपये इन वाहनों के लिए रखे गए हैं।

वित्त मंत्री के इस ऐलान से उम्मीद है कि भविष्य में भारत में इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो सकती हैं। ऐसा मानने के पीछे वजह यह है कि किसी भी इलेक्ट्रिक कार का सबसे महंगा हिस्सा उसका बैटरी पैक होता है। ऐसे में अगर बैटरी सस्ती हो जाती है तो कार की कीमत भी कम हो जाएगी।

लिथियम की सस्ती कीमत बैटरी की निर्माण लागत को प्रभावित करेगी। इससे लिथियम-आयन बैटरी सस्ती हो जाएंगी। अगर कार की बैटरी सस्ती हो जाती है, तो वाहन निर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम कर सकते हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रिक कार खरीदने की शुरुआती लागत बहुत अधिक है। इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च कीमत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में बाधा डालने वाले कई कारणों में से एक है। भारत सरकार इस दशक के अंत तक देश की कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की 30 प्रतिशत पैठ हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

बजट 2024 में की गई घोषणाएं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफी अहम हैं। लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में कमी और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के जरिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और बिक्री को बढ़ावा देने की कोशिश की है। इन बदलावों से न सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम होंगी बल्कि देश में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना भी संभव होगा। आने वाले समय में ये बदलाव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नई दिशा देने में अहम साबित हो सकते हैं।

तुर्की की नीति में बदलाव से यूरोपीय संघ के टैरिफ का सामना कर रहे चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा जीवनदान

परिवहन विशेष न्यूज

चीनी आर्थिक मीडिया आउटलेट यिकाई की 22 तारीख को आईरिपोर्ट के अनुसार, तुर्की, चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों पर यूरोपीय संघ (ईयू) के उच्च टैरिफ के खिलाफ चीन के लिए एक रणनीतिक बाईपास के रूप में उभरा है। यह विकास पिछले एक साल में तुर्की और चीन दोनों द्वारा टैरिफ समायोजन और रणनीतिक कदमों की एक श्रृंखला के बाद हुआ है।

पिछले साल मार्च में तुर्की ने टैरिफ में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की जिसमें 50% टैरिफ दर लागू की गई, जिसमें चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त 40% टैरिफ शामिल था। यह कदम तुर्की की अपने घरेलू बाजार की रक्षा करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा था। हालांकि, पिछले महीने की 8 तारीख को तुर्की ने इन टैरिफ को चीनी निर्मित ऑटोमोबाइल पार्ट्स को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया, जिससे चीनी आयात के खिलाफ अपनी व्यापार नीतियों को और सख्त कर दिया।

इस महीने की शुरुआत में स्थिति में नाटकीय मोड़ तब आया जब तुर्की ने ₹आयात पर अतिरिक्त शुल्क पर संशोधन आदेश₹ शीर्षक से एक राष्ट्रपति डिक्री जारी की। इस डिक्री ने पिछले उच्च शुल्कों को उलट दिया, इसके बजाय देश में निवेश करने वाले विदेशी ऑटोमोबाइल निर्माताओं पर केवल मौजूदा 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया, जिसमें चीन के निर्माता भी शामिल हैं। इस नीतिगत बदलाव को विदेशी निवेश को आकर्षित करने और तुर्की के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा गया। 12 जून को यूरोपीय संघ आयोग ने चीनी अधिकारियों से अनुचित सब्सिडी का हवाला देते हुए कम से कम चार महीनों के लिए चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ दर को न्यूनतम 27.4% और अधिकतम 47.6% तक बढ़ाने का फैसला किया। इस फैसले ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं पर काफी दबाव डाला है, जिससे उन्हें यूरोपीय बाजार में वैकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

चीन यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ व्यक्तिगत संपर्कों और बाईपास मार्गों को सुरक्षित करके अंतिम यूरोपीय संघ टैरिफ निर्णय को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। तुर्की इस रणनीति में एक प्रमुख विकल्प के रूप में उभरा है। शंघाई में फुडन विश्वविद्यालय के तहत मध्य पूर्व अनुसंधान केंद्र के एक शोधकर्ता झोउ झिचांग ने कहा, ₹तुर्की इलेक्ट्रिक वाहनों सहित नए ऊर्जा वाहन विनिर्माण उद्योग को विकसित करने और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को निर्यात करने के लिए कम टैरिफ दरों के साथ चीनी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य बना रहा है।"

इस महीने की शुरुआत में तुर्की के राष्ट्रपति के फरमान की घोषणा के तुरंत बाद चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी बीवाईडी ने तुर्की में एक स्थानीय कारखाना स्थापित करने के लिए एक निवेश अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बीवाईडी कारखाने के 2026 के अंत तक स्थापित होने, 5,000 स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देने और सालाना 150,000 वाहनों का उत्पादन करने की उम्मीद है। इस निवेश को चीन और तुर्की के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और उच्च यूरोपीय संघ के टैरिफ के बावजूद चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के लिए एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों को इस बात पर मतदान करना है कि क्या इन अनंतिम टैरिफ को ₹अक्टूबर के आसपास₹ निश्चित टैरिफ में बदला जाए। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है, तो यूरोपीय संघ की बढ़ी हुई टैरिफ दरें पांच साल तक बनी रहेंगी, जिससे यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापार की गतिशीलता और भी जटिल हो जाएगी।

ईवी मंदी के बीच ऑडी हाइब्रिड लाइन-अप का करेगी विस्तार

परिवहन विशेष न्यूज

ईवी अपनाने में वैश्विक मंदी के बीच ऑडी ने खुलासा किया है कि वह आने वाले वर्षों में हाइब्रिड वाहनों की अपनी रेंज को अपग्रेड और विस्तारित करेगी। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दहन कारों से ईवी में परिवर्तन शुरू में अपेक्षा से कहीं अधिक समय ले रहा है। मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और बीवाईडी सहित कई अन्य ऑटो प्रमुखों ने भी इसी तरह के कारणों से वैश्विक योजनाओं में इस तरह के बदलावों की घोषणा की है। ऑडी नए PHEV पावरट्रेन विकसित कर रही है, लेकिन अपनी EV योजनाओं पर कायम रहेगी।

कंपनी का अंतिम दहन इंजन मॉडल 2026 में बिक्री के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। ऑडी अभी भी 2033 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल लाइन-अप करने की अपनी मूल समय सीमा के करीब है, लेकिन यह विस्तार संभवतः धीरे-धीरे होगा। तब तक कंपनी अपने प्रत्येक मुख्य सेगमेंट में दहन और इलेक्ट्रिक दोनों विकल्प पेश करना जारी रखेगी। मीडिया सूत्रों से बात करते हुए ऑडी के सीईओ गर्नोट डोएलनर ने कहा कि कंपनी की रणनीति ₹अगले 10 वर्षों के लिए तैयार रहने₹ की है, जिसके बारे में उनका अनुमान है कि यह दहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच एक विस्तारित संक्रमण चरण होगा। हाइब्रिड की प्रासंगिकता और उनकी बढ़ती मांग को देखते हुए, ऑडी अब अपने अगली पीढ़ी के PHEV मॉडल के लिए हाइब्रिड पावरट्रेन की एक नई रेंज विकसित कर रही है। ये बहुत बड़ी बैटरी से लैस होंगे जो अकेले इलेक्ट्रिक पावर पर लगभग 100 किमी की रेंज प्रदान करेंगे।

हाइब्रिड पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के बावजूद ऑडी अपनी दीर्घकालिक ईवी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है। ₹हम अभी बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों में धीरे-धीरे नकारात्मक रुझान देख रहे हैं, लेकिन बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में अभी भी सकारात्मक वृद्धि दर है, इसलिए यह सिर्फ इतना है कि विकास दर धीमी हो गई है। अगले 10 वर्षों के लिए, कम से कम, हमारे पास तीन प्रासंगिक ड्राइवट्रेन के साथ एक संक्रमण चरण होगा: अत्यधिक कुशल आईसीई ड्राइवट्रेन, प्लग-इन हाइब्रिड (विशेष रूप से चीन और उत्तरी अमेरिका में महत्वपूर्ण हो रहे हैं), और बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहन। सकारात्मक संदेश यह है कि हम लचीले हैं," डॉलनर ने कहा।

लखनऊ के ई-रिक्शा चालक बने दिव्यांगों और जरूरतमंदों का सहारा

परिवहन विशेष न्यूज

लखनऊ की सड़कों पर ई-रिक्शा चालकों का उत्पात आए दिन देखने को मिलता है। ई-रिक्शा का नाम आते ही लोगों के दिमाग में इसे चलाने वालों की गलत छवि बन गई है, लेकिन एक ई-रिक्शा चालक ऐसा भी है जो दिव्यांगों, बुजुर्गों और जरूरतमंदों का सहारा बन गया है। वह उन्हें अपने ई-रिक्शा में मुफ्त सवारी कराता है। उसका नाम सुनील शुक्ला है जो मूल रूप से गोंडा के रहने वाले हैं, लेकिन अब लखनऊ में रहते हैं। सुनील कहते हैं कि उन्हें इस सेवा से आत्म संतुष्टि मिलती है, जिससे उन्हें काफी शांति मिलती है।

सुनील वर्तमान में इंदिरा नगर के मुलायम नगर इलाके में परिवार संग रहते हैं। वह यहां करीब पांच-छह सालों से बैट्री रिक्शा चालकर अपना घर चला रहे हैं। सुनील का कहना है कि करीब 11 माह पहले उन्होंने दिव्यांगों और बेसहारा बुजुर्ग महिला व पुरुषों की मदद करने के लिए फ्री सेवा की पहल शुरू की थी। उन्होंने अपने ई-रिक्शे पर एक पोस्टर लगाया, जिसमें लिखा कि वह दिव्यांगों और बेसहारा बुजुर्ग महिला व पुरुषों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए फ्री सेवा देते हैं। इस पहल के चलते सुनील अब तक 11 माह में करीब 748 लोगों की मदद कर चुके हैं।

एक दिन में 8 से 10 लोगों की सेवा सुनील के अनुसार, वह अपना रिक्शा तय रूट पर ही चलाते हैं, जहां दिन में कई जरूरतमंदों की मदद करते हैं। लेकिन खास तौर पर वह अपना रिक्शा इलाके में स्थित अस्पतालों के बाहर लेकर खड़े हो जाते हैं, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएं और उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचा दें। वह करीब 8 से 10 लोगों की रोजाना मदद करते हैं।

सुनील ने बातचीत में बताया कि उनके पास अभी एक ही ई-रिक्शा है, जो ईएमआई पर है। इसकी किश्तें पूरी होने के बाद वह और भी ई-रिक्शे निकलवाकर ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद करेंगे और उनमें से कुछ वाहनों को सिर्फ बेसहारा व जरूरमंदों की मदद के लिए फ्री चलवाएंगे।

सुनील का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि जब किसी दिव्यांग व बेसहारा बुजुर्ग की मदद करते हैं तो वह उनको निस्वार्थ सेवा देख भावुक हो जाते हैं। वे लोग बस यही कहते हैं कि हम लोगों को अपनों ने तो बेघर कर दिया, कम से कम तुम हमारे जैसे लोगों को अपना होने का एहसास दे रहे हो। सुनील के इस सराहनीय कार्य के दौरान ऐसे भावुक पलों के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए हैं।

पीली और सफेद पट्टी देखकर ही ई-रिक्शा में बैठें, नहीं तो पड़ सकता हैं उतरना

परिवहन विशेष न्यूज

ग्वालियर में ई-रिक्शा के संचालन के लिए रंग तय कर दिए गए हैं। दिन में चलने वाले ई-रिक्शा पर पीली पट्टी होगी और रात में चलने वाले ई-रिक्शा पर सफेद पट्टी होगी। पहले दो महीने तक पहले से पंजीकृत ई-रिक्शा को दिन की शिफ्ट में चलाया जाएगा।

यह जानकारी नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में दी। बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान ने ई-रिक्शा के संचालन के लिए तैयार की गई योजना को धरातल पर लाने के लिए सात दिन के भीतर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दोपहर 3 से रात 3 बजे एवं रात 3 से दोपहर 3 बजे तक दो शिफ्टों में रिक्शा चलाने का निर्णय लिया गया था। दो माह बाद ई-रिक्शा की शिफ्ट में बदलाव होगा।

पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को डेढ़ साल बाद आखिरकार मिलेगा प्रोत्साहन राशि

परिवहन विशेष न्यूज

पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। परिवहन विभाग सभी लंबित मामलों में प्रोत्साहन जारी करना शुरू कर देगा। डेढ़ साल बाद आखिरकार विभाग ने अपना पोर्टल तैयार कर लिया है और एक महीने के अंदर लोगों को यह राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। विभाग ने पिछले साल फरवरी में पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की थी, जिसमें दोपहिया और तिपहिया वाहनों को प्रोत्साहन जारी करने का फैसला किया गया था।

पोर्टल तैयार न होने के कारण विभाग लोगों को प्रोत्साहन राशि जारी नहीं कर पा रहा था। यही कारण है कि प्रोत्साहन राशि के प्रकरण तैयार कर विभाग को भेजे जा रहे थे, लेकिन पोर्टल न होने के कारण राशि जारी नहीं हो पा रही थी। अब विभाग ने एचडीएफसी बैंक की मदद से यह पोर्टल तैयार किया है, ताकि लोगों को प्रोत्साहन राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को ई-वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। लोग ई-वाहन खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

पंजाब सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की थी, जिसे फरवरी 2023 में जारी किया गया था। पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ई-वाहनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना, बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और राज्य में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को आकर्षित करना था। पॉलिसी तीन साल के लिए जारी की गई थी, जिसमें इस अवधि के दौरान दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन जारी करने की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा तिपहिया और ई-साइकिल समेत अन्य श्रेणियों में यह प्रोत्साहन अलग से तय किया गया था। पॉलिसी की हर साल समीक्षा करने की भी योजना है।

3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि तय की गई है, जो अधिकतम 10,000 रुपये है। यह प्रोत्साहन राशि पहले 50,000 पंजीकृत दोपहिया वाहनों को दी जानी है। इसी प्रकार ई-श्री व्हीलर्स को प्रोत्साहन देने के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रति किलोवाट घंटा बैटरी क्षमता पर 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो अधिकतम 30,000 रुपये है। यह प्रोत्साहन राशि पहले 5,000 पंजीकृत ई-श्री व्हीलर्स को दी जानी है। इसी प्रकार, ई-रिक्शा और ई-कार्ट पर भी यह प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रति किलोवाट घंटा बैटरी क्षमता पर 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की जाती है, जो अधिकतम 15,000 रुपये है। यह प्रोत्साहन राशि पहले 10,000 पंजीकृत ई-कार्ट्स को दी जाएगी।

अर्थव्यवस्था को तीव्र गति एवं महाशक्ति बनाने वाला बजट

ललित गर्ग

भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से यह बजट कारगर साबित होगा, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, रोजगार के नये अवसर सामने आयेंगे, उत्पाद एवं विकास को तीव्र गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम सम्पूर्ण बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, उनकी ओर से प्रस्तुत यह बजट एक मौलिक सोच एवं दृष्टि से दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिये आगे की राह दिखाने वाला है। संभावना है कि इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, नौकरीपेशा का थोड़ी राहत, बुनियादी ढांचे में निवेश, पर्यटन को बढ़ावा, आदिवासी उन्नयन, क्षमता विस्तार, हरित एवं कृषि विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी, मोदी के नये भारत-सशक्त भारत-विकसित पर बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने सरकार की 9 प्राथमिकताओं -खेती में उत्पादकता और मजबूती बढ़ाना, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, मानव संसाधन का समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्नोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स का ऐलान किया है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति देगा। बजट में जहां बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है वहीं महंगाई को नियंत्रित करने की मंशा साफ दिखाई दी है। विकास, स्टार्टअप और रोजगार सृजन के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में सहायक बनेगा। सातवीं बार बजट प्रस्तुत कर वित्तमंत्री सीमारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।

सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है। अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो इस बजट से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इस बजट में मध्यम वर्ग को लम्बे अन्तराल के बाद 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में भी कुछ अहम बदलाव करने का एलान किया है। मौजूदा नियमों के तहत एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस लिमिट को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की घोषणा की। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा। मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे पहुंचाने का लक्ष्य है। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से यह बजट कारगर साबित होगा, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, रोजगार के नये अवसर सामने आयेंगे, उत्पाद एवं विकास को तीव्र गति मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद इस बजट प्रावधानों के माध्यम से देश को स्थिरता की तरफ ले जाते दिखाई पड़ रहे हैं। बजट हर वर्ष आता है। अनेक विचारधाराओं वाले वित्तमंत्रियों ने विगत में कई बजट प्रस्तुत किए। पर हर बजट लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर ही जाता रहा है। लेकिन इस बार बजट ने अर्थव्यवस्था में नयी परम्परा के साथ राहत की सांसें दी है तो नया भारत- सशक्त भारत-विकसित के निर्माण का संकल्प भी व्यक्त किया है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रेलों का विकास, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ किसानों, आदिवासियों, गांवों और गरीबों को ज्यादा तवज्जो दी गयी है। सच्चाई यही है कि जब तक जमीनी विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की गति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। इस बार के बजट से हर किसी ने काफी उम्मीदें लगा रखी थीं और उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। विशेषतः नौकरीपेशा लोगों ने राहत की सांस ली है।

संभवतः इस बजट को नया भारत निर्मित करने की दिशा में लोक-कल्याणकारी बजट कह सकते हैं। यह बजट वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशाओं को भी उद्घाटित करता है। आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है बल्कि यह देश को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण एवं दूरगामी सोच से जुड़ा कदम है। बजट के सभी प्रावधानों एवं प्रस्तावों में जहां 'हर हाथ को काम' का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत यह बजट निश्चित ही अमृत बजट है। जिसमें भारत के आगामी 25 वर्षों के समग्र एवं बहुमुखी विकास को ध्यान में रखा गया है। बीते कुछ सालों में नरेन्द्र मोदी ने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।

आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। बजट में टूरिज्म पर विशेष बल दिया गया है। पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है।. भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। सरकार ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगी, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आशा के अनुरूप ही बजट का फोकस किसानों, आदिवासियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, रोजगार, युवाओं की अपेक्षाओं, विकास और ग्रामीण क्षेत्र एवं पर्यटन पर रखा है। अपने ढांचे में यह पूरे देश का बजट है, एक आदर्श बजट है। इसका ज्यादा जोर सामाजिक विकास पर है। अक्सर बजट में राजनीति, वोटनीति तथा अपनी व अपनी सरकार की छवि-वृद्धि करने के प्रयास ही अधिक दिखाई देते है लेकिन बावजूद यह बजट राजनीति प्रेरित नहीं, देश प्रेरित है। इस बजट में जो नयी दिशाएं उद्घाटित हुई है और संतुलित विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था का जो संकेत दिया गया है, सरकार को इन क्षेत्रों में अनुकूल नतीजे हासिल करने पर खासी मेहनत करनी होगी।

संपादक की कलम से

बेरोजगारी-महंगाई से मुक्ति मिले

आज तीसरी मोदी सरकार का पहला संपूर्ण, राष्ट्रीय बजट संसद में पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब भी बजट बनाया है। बजट से देश को कई उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। बजट का फोकस क्या होगा, यह बजट को पढने के बाद ही स्पष्ट होगा। देश के युवा की अहम समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी की राष्ट्रीय दर 9 फीसदी से अधिक हो गई है। हालांकि सरकारी आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। करीब 80 करोड़ भारतीयों के हाथ में स्थायी रोजगार नहीं है अथवा वे बेरोजगार हैं। मनरेगा का कायाकल्प बहुत जरूरी है, हालांकि पिछले बजट में उसकी राशि घटा दी गई थी। बेरोजगारी से महंगाई और गरीबी जुड़ी हैं। हालांकि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्रीय दावे हैं कि महंगाई की औसत दर 5 फीसदी से कम है, लिहाजा वह नियंत्रण में है, लेकिन 127 रुपए किलो टमाटर मिले और अधिकतर दालें 150 रुपए किलो से अधिक बिक रही हैं, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? क्या ये दाम सस्ती व्यवस्था के सूचक हैं? महंगाई के साथ जमाखोरी और कालाबाजारी कितनी है, शायद बजट में उनका उल्लेख न हो, लेकिन महंगाई एक राष्ट्रीय समस्या है, जिसे बजट में संबोधित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पद को ग्रहण करने से पहले देश को आश्वस्त किया था कि महंगाई पर लगाम कसी जाएगी। औसतन किसान बहुत गरीब है, लिहाजा प्रधानमंत्री ने उनकी आमदनी दोगुनी करने का वायदा किया था। वह अभी तक तो नहीं हुई है, अलबत्ता कुछ प्रयास जरूर किए गए हैं। चर्चाएं जारी हैं कि किसान की सम्मान निधि को 6000 रुपए सालाना से बढ़ाया जा सकता है। भारत ने 48,389 करोड़ रुपए का बासमती चावल निर्यात किया है। गेहूं और अन्य उपजों की स्थिति डांवाडोल रहती है, क्योंकि सरकार की नीतियां बदलती रहती हैं। इतना निर्यात करने वाला किसान अब भी गरीब है, यह विरोधाभासी सवाल है।

इसके मायने हैं कि किसान से औने-पौने दाम पर उपज खरीदी जाती है और फिर सरकारी एजेंसियां उसे महंगे दामों पर बाहर देशों को बेचती हैं। यही घरेलू बाजार में होता है। 'किसान कार्ड' की सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। कुछ सबसिडी भी घोषित की जा सकती है, लेकिन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी पर सरकार कोई ठोस घोषणा करेगी? सरकारी अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर की स्थिति क्या रहेगी? आधारभूत ढांचे और विनिर्माण क्षेत्रों की प्रगति के लिए कितना बजट तय किया जाएगा, यह भी महत्वपूर्ण संभावना है। लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों के लिए सरकार कितना बजट आवंटित करेगी, यह इसलिए अहम है, क्योंकि ये उद्योग कोरोना महामारी के दौरान तालाबंदी की स्थिति में आ गए थे। चूंकि इन उद्योगों में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं, लिहाजा सरकार इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार करना चाहेगी! देश पर करीब 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इतना कर्ज क्यों लिया गया और अब भुगतान की स्थिति क्या है, क्या बजट में इसका खुलासा किया जाएगा। बजट की दृष्टि से राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा कितना है, बजट में इसका खुलासा तो किया जाता है, लेकिन ये अपेक्षित औसत में कब आएंगे, देश को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए।

बेशक बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, अंतरिक्ष, विशेष अभियानों आदि पर पर्याप्त दिया जाना चाहिए, ताकि हम भावी आपदाओं के लिए पूरी तरह तैयार रह सकें। बजट में औसत नागरिक को आयकर पर छूट पर्याप्त है, लेकिन देश में आर्थिक असमानता की खाई को भरा जाना चाहिए। इसके अलावा, शिक्षा, गृह, निजी ऋणों को बैंकों में अपेक्षाकृत सस्ता किया जाना चाहिए। इन पर ब्याज दरें अब भी काफी हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के विभिन्न आकलनों के मुताबिक, भारत की सालाना आर्थिक विकास दर 7-8 फीसदी है, जो विश्व में सर्वाधिक है। भारत दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसका उल्लेख बजट में भी होगा, लेकिन विकसित बनाम गरीब का इतना गहरा विरोधाभास भारत में क्यों है? हमें उम्मीद है कि बजट के लिए यह सवाल स्वीकार्य नहीं होगा। यह सुखद स्थिति है कि कच्चे तेल के आयात पर खर्च में काफी कमी आई है, क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। फिर भी 144 करोड़ की आबादी के लिए बजट सुखद होना चाहिए। प्रतीक्षारत हैं।

राय

इस डिजिटल युग में भी पुस्तकालयों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है

विजय गर्ग

हालाँकि इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, छात्रों को पुस्तकालयों का उपयोग करने और उनमें मौजूद पुस्तकों से आवश्यक जानकारी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एक पुस्तकालय एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुकूल शांत और शांत वातावरण प्रदान करता है और अंतर्निहित सीखने के कौशल को उत्तेजित करता है।। एक समय, कॉलेजों में पुस्तकालय छात्रों और शिक्षकों से भरे रहते थे और सीखने की अधिकांश प्रक्रिया यहीं होती थी। हालाँकि, इंटरनेट के आगमन के साथ, कॉलेजों में पुस्तकालय लगभग खाली हैं और छात्र अपना अधिकांश समय वेब ब्राउज़ करने में बिताते हैं। इनमें से बहुत कुछ उपयोगी या अनुत्पादक नहीं होने के अलावा, इसने उनके ध्यान की अवधि को भी प्रभावित किया है।

इंटरनेट ब्राउज़ करना और लाइब्रेरी में किताब पढ़ना एक दूसरे से बहुत अलग हैं। वेब पर, प्रदर्शन पर मौजूद कई विकल्पों और संबंधित साइटों के सुझावों से व्यक्ति का ध्यान भटक जाता है। जबकि, एक पुस्तकालय एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुकूल शांत वातावरण प्रदान करता है और अंतर्निहित सीखने के कौशल को उत्तेजित करता है। किसी शांत जगह पर किताब पढ़ने और महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करने से याददाश्त बढ़ाने और प्रभावी ढंग से सीखने में मदद मिलती है। इससे किसी परीक्षण या परीक्षा में छात्र के प्रदर्शन में मदद मिलती है।

प्रेरणास्रोत: पुस्तकालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की भी भूमिका होती है। शिक्षकों को अपने काम के लिए पुस्तकालय का उपयोग करके रोल मॉडल के रूप में काम करना चाहिए। हालाँकि अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों ने पुस्तकालय का एक घंटा अनिवार्य कर दिया है, लेकिन छात्र या तो वहाँ नहीं जाते हैं या वे कमरे में बैठकर बातें करते हैं या अपने मोबाइल फोन पर खेलते हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे गैजेट्स को लाइब्रेरी में ले जाने की अनुमति नहीं है, जिससे छात्र अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

कक्षा में, घर में और पुस्तकालय में अध्ययन करने में बहुत अंतर है। उत्तरार्द्ध सबसे बड़ा प्रभाव प्रदान करता है और शिक्षकों को छात्रों पर सूक्ष्म अंतर पर जोर देने और उन्हें नियमित रूप से पुस्तकालय का उपयोग करने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यह असाइनमेंट देकर किया जा सकता है जिसमें छात्रों को पुस्तकालय में विशिष्ट पुस्तकों का संदर्भ देना शामिल होगा। इससे स्क्रीन पर न दिखने वाली चीज़ को पढ़ने की आदत भी विकसित होगी।

पढ़ना केवल पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं और स्वयं के विकास के लिए पढ़ने और कॉलेज समय के बाद पुस्तकालय में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन छात्रों के लिए जो गेट या यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यह बहुत मददगार होगा।

आज आम धारणा है कि सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। लेकिन इस डिजिटल युग में भी पुस्तकालयों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

किशोर शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण

विजय गर्ग

(भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) किशोरों के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन और सीखने के परिणामों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरी है)

किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण है जहां विश्वास और जीवन कौशल बनते हैं, जो एक बच्चे के भविष्य के लिए पथ निर्धारित करते हैं। इस अवधि के दौरान भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास एक खुशहाल और सफल जीवन की नींव रखता है। शिक्षा के निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) किशोरों के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन और सीखने के परिणामों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभरी है। जैसे-जैसे किशोर अपने प्रारंभिक वर्षों की जटिलताओं से जूझते हैं, भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां, हम यह पता लगाएंगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता शैक्षणिक सफलता को कैसे प्रभावित करती है और किशोरों के बीच ईआई को बढ़ावा देने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस बात पर जोर दिया गया है कि ₹इस स्तर पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने का मतलब है कि आप एक खुशहाल और सफल जीवन की नींव रख रहे हैं।₹ भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझना किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण विकासात्मक चरण है जहां विश्वास और जीवन कौशल बनते हैं, जो एक बच्चे के भविष्य के लिए पथ निर्धारित करते हैं। इस अवधि के दौरान भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास एक खुशहाल और सफल जीवन की नींव रखता है। ₹इस स्तर पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने का मतलब है कि आप एक खुशहाल और सफल जीवन की नींव रख रहे हैं।₹ अनुसंधान इंगित करता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता अल्पकालिक और दीर्घकालिक शैक्षणिक प्रदर्शन और सीखने के परिणामों दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। उच्च ईआई वाले किशोर भावनाओं को प्रबंधित करने, रिश्ते बनाने और सामाजिक जटिलताओं से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। यह क्षमता उनकी पढ़ाई में बेहतर एकाग्रता और प्रेरणा में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान छात्र यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने, चुनौतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और प्रभावी समस्या-समाधान रणनीतियों का उपयोग करने में अधिक कुशल होते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में चुनौतियाँ हालाँकि, किशोरों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ₹किशोर होना बवंडर में फंसने जैसा है,₹ किशोरावस्था की तीव्र भावनात्मक उतार-चढ़ाव की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं। हार्मोनल परिवर्तन, सहकर्मी और माता-पिता का दबाव, और सामाजिक स्वीकृति की इच्छा आत्म-जागरूकता और प्रामाणिकता में बाधा बन सकती है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल मीडिया का प्रभाव, साइबरबुलिंग और जीवन के अवास्तविक चित्रण की क्षमता के साथ, सहानुभूति और स्वस्थ पारस्परिक कौशल के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। शिक्षकों की भूमिका किशोरों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पाठ्यक्रम में सामाजिक-भावनात्मक शिक्षण (एसईएल) कार्यक्रमों, आत्म-जागरूकता, आत्म-नियमन, लक्ष्य निर्धारण, लचीलापन, समस्या-समाधान और प्रभावी संचार जैसे शिक्षण कौशल को शामिल कर सकते हैं। एक सहायक कक्षा वातावरण बनाना जहाँ छात्र अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अपने अनुभवों को साझा करने में सुरक्षित महसूस करें, महत्वपूर्ण है। यह शिक्षकों के भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यवहार को मॉडल करने के महत्व पर जोर देता है, यह प्रदर्शित करता है कि संघर्षों और तनाव को रचनात्मक तरीके से कैसे संभालना है। समूह गतिविधियों और सहयोगी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने से छात्रों को पारस्परिक कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, प्रतिबिंब और दिमागीपन प्रथाओं के लिए अवसर प्रदान करने से भावनात्मक विनियमन और आत्म-जागरूकता बढ़ सकती है, एक अच्छी तरह से भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा मिल सकता हैविकास। माता-पिता और शिक्षकों के बीच सहयोग किशोरों में विकास की मानसिकता विकसित करने के लिए माता-पिता और शिक्षकों को सहयोग करना चाहिए। प्रयास, दृढ़ता और लचीलेपन को लगातार प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण है। माता-पिता चुनौतियों को स्वीकार करके और गलतियों से सीखकर एक विकास मानसिकता का मॉडल तैयार कर सकते हैं, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं जो पूर्णता पर सुधार को महत्व देता है। शिक्षक अपने शिक्षण में विकास मानसिकता सिद्धांतों को एकीकृत कर सकते हैं, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं और प्रगति का जश्न मना सकते हैं। प्रभावी सहयोग में रणनीतियों को संरेखित करने और घर और स्कूल दोनों में विकासोन्मुख संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए माता-पिता और शिक्षकों के बीच नियमित संचार शामिल है। विकास मानसिकता सिद्धांतों पर केंद्रित कार्यशालाएं और बैठकें इस साझेदारी को बढ़ा सकती हैं, जिससे किशोरों के लिए लगातार समर्थन और प्रोत्साहन सुनिश्चित हो सकेगा। द बिगर पिक्चर अंत में, एक समग्र शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए पाठ्यक्रम में सामाजिक-भावनात्मक कौशल को शामिल करने का महत्व। वह जोर देकर कहती हैं, ₹शिक्षा तभी समग्र होगी जब हम सामाजिक-भावनात्मक कौशल विकास को भी महत्व देना शुरू करेंगे।₹ भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देकर, हम किशोरों को शैक्षणिक और जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस कर सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

तकनीकी आजादी की ओर बढ़े भारत

विजय गर्ग

पिछले दस साल में भारत की जीडीपी लगभग दोगुनी होकर ३.5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। हमारा लक्ष्य है, २047 तक भारत विकसित देश बने। अगर हम अपनी आर्थिक विकास दर को आठ प्रतिशत से बढ़ाकर 1२ प्रतिशत कर लें, तो भारत 50 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। दुनिया भर में तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, खासकर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और नई ऊर्जा के क्षेत्र में। हमारे समकक्ष देश, जैसे चीन, नई तकनीक में भारी निवेश कर कर रहे हैं, पारंपरिक उद्योगों में बदलाव ला रहे हैं और नए क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। त के विकास और प्रतिस्पर्द्धा में आगे रहने के लिए हमें एआई और नई ऊर्जा जैसी तकनीक को प्राथमिकता देनी होगी। इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। ध्यान रहे, साल 1947 में हमने अपनी राजनीतिक आजादी पाई थी और साल भारत २047 में हमें अपनी तकनीकी आजादी हासिल करनी है। हमें तकनीकी उन्नति के लिए अपनी खुद की रणनीति बनानी होगी। अपने देश में तकनीक का यह उपयोग सिर्फ आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए भी होना चाहिए।

भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक डिजिटल हो चुकी है, लेकिन कंप्यूटिंग में हमारी भागीदारी अभी भी बहुत कम है। आईटी सेवाओं में हमारी बड़ी सफल के बावजूद ३० ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भारत का हिस्सा सिर्फ एक प्रतिशत है। यहां निवेश की बड़ी जरूरत है। भारत अभी भी अनोखी ताकतों से लैस है। विश्व के सबसे बड़े डेवलपर समुदाय में से एक भारत में है। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक सिलिकॉन डिजाइनर, विशाल मात्रा में उत्पन्न डाटा, और दुनिया का सबसे बड़ा आईटी उद्योग हमें एआई में अग्रणी बनाने की स्थिति में लाते हैं। हम एआई महाशक्ति में बदल सकते हैं। ठीक वैसे ही, जैसे चीन ने वैश्विक विनिर्माण के क्षेत्र में क्रांति ला दी। एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भारत को डाटा, कंप्यूटिंग और एल्गोरिदम में विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहिए। भारत दुनिया का २० प्रतिशत डाटा बनाता है, लेकिन हमारा 80 प्रतिशत डाटा विदेश में स्टोर किया जाता है, एआई में प्रोसेस किया जाता है और फिर डॉलर में भुगतान करके वापस आयात किया जाता है। यह डाटा कॉलोनाइजेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर-तरीकों की याद दिलाता है, जहां भारत के कच्चे माल का दोहन करके, उन्हें प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में महंगे दामों पर भारतीयों को बेचा जाता था। आज, हमारे डिजिटल कच्चे माल, यानी डाटा का इसी तरह से लाभ उठाया जा रहा है। हमें अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके गोपनीयता संरक्षित डाटासेट बनाना चाहिए। हम अपनी डीपीआई की सफलता (जैसे, यूआईडीएआई, यूपीआई, ओएनडीसी) पर आधारित होकर एक नई दुनिया की सबसे बड़ी ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, जो भारत के सिद्धांतों पर आधारित हो।

बेशक, साल २०३० तक 50 गीगावाट डाटा सेंटर की क्षमता पाने के लिए २०० अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। यह हासिल करने योग्य लक्ष्य है। भारत सिलिकॉन डेवलपमेंट और डिजाइन टैलेंट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। फिर भी, हमारे पास भारत में डिजाइन किए गए चिप्स की कमी है। हमें इंडस्ट्री लीडिंग चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स और रिसर्च-लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से सरकारी प्रोत्साहन की जरूरत है, ताकि रोजगार बढ़े, भारत में काम करने के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभाओं और बेहतरीन वैज्ञानिकों को आकर्षित किया जा सके। पर्याप्त रोजगार वाले विकसित भारत के लिए नई ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और तकनीक का भी विकास होना चाहिए। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य बदल रहा है। भारत को इस बदलाव में सबसे आगे रहना चाहिए। नई ऊर्जा का पूरा इकोसिस्टम तीन स्तंभों पर टिका है रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक वाहन। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब अक्षय ऊर्जा में भारत की ताकत बढ़नी चाहिए। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता २014 में 7२ गीगावाट से बढ़कर २0२३ में 175 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। सोलर एनर्जी क्षमता ३.8 गीगावाट से बढ़कर 88 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। वैसे, हम इस मोर्चे पर पीछे हैं। हमें २०३० तक 500 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। अक्षय ऊर्जा को प्रभावी बनाने के लिए हमें इसे मजबूत बैटरी स्टोरेज से जोड़ना होगा। अभी हमारी बैटरी स्टोरेज क्षमता सिर्फ दो गीगावाट है, जबकि चीन की 1,700 गीगावाट है। अपने अक्षय ऊर्जा ग्रिड को पावर देने और 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन के लक्ष्य को पाने के लिए 1,000 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें, भारत में अभी प्रति 1,000 लोगों पर २०० से भी कम इलेक्ट्रिक वाहन हैं। चीन के तीन करोड़ की तुलना में भारत में हर साल सिर्फ बीस लाख ईवी बेचे जाते हैं। भारत को साल २०३० तक पांच करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह बदलाव पर्यावरण को स्वच्छ बनाएगा, परिवहन लागत को कम करेगा। वर्तमान में, सौर ऊर्जा उत्पादन, लिथियम सेल उत्पादन और ईवी उत्पादन जैसे न्यू न्यू एनर्जी इकोसिस्टम का 90 प्रतिशत हिस्सा चीन में है। अपनी खुद की तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला बनाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक ऊर्जा कुशल बना सकते हैं और देश में लाखों नौकरियां पैदा कर सकते हैं।

भविष्य की तकनीकों में महारत हासिल करना ही भारत के लिए ग्लोबल लीडरशिप का रास्ता है। हमें पीछे नहीं रहना है, बल्कि समकक्षों को पीछे छोड़कर एआई और नई ऊर्जा के क्षेत्र में लीडर बनना है। यह भारत को दुनिया में तकनीकी रूप से सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था में बदलने का मौका है। सबसे बड़ी बात कि इससे देश में करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें समाज के सभी तबकों के एकजुट प्रयास की जरूरत है। जिस तरह हर भारतीय ने स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई थी, उसी तरह अब हमारे तकनीकी भविष्य के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका है। यह साहसिक कदम उठाने और बड़े सपने देखने का समय है। हमें तत्काल काम शुरू करना होगा, ताकि हम उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

विनिवेश के जरिये 50 हजार करोड़ जुटाने का लक्ष्य

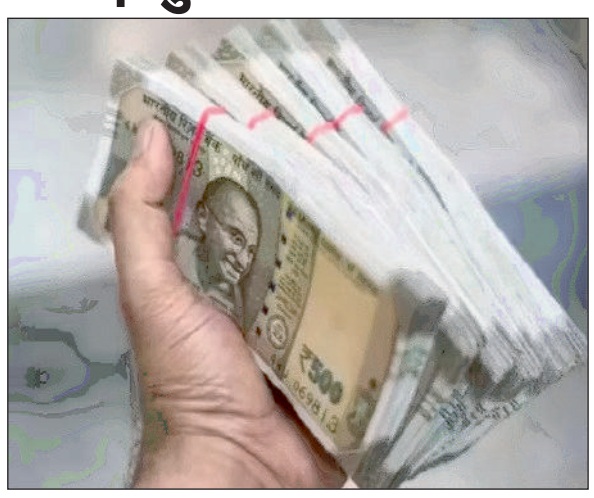

तुहिन कांत ने बताया कि इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (CPSE) को 56260 करोड़ रुपये का लाभांश मिलने का अनुमान है। बजट में आरबीआई बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से चालू वित्त वर्ष में 232874 करोड़ रुपये का लाभांश मिलने की उम्मीद जताई गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान को घटाकर 30 हजार करोड़ रुपये किया गया है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चालू वित्तवर्ष 2024-25 के दौरान विनिवेश और संपत्ति मौद्रिकरण के जरिये 50 हजार करोड़ रुपये जुटाए जाने का लक्ष्य रखा है। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन प्रबंधन विभाग (DIPAM) सचिव तुहिन कांत ने यह जानकारी दी।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से मिलेगा इतना लाभ

तुहिन कांत ने बताया कि इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (CPSE) को 56,260 करोड़ रुपये का लाभांश मिलने का अनुमान है। अंतरिम बजट में सीपीएसई से 48 हजार करोड़ रुपये का अनुमान जताया गया था।

आरबीआई, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ये उम्मीद

बजट में आरबीआई, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से चालू वित्त वर्ष में 2,32,874 करोड़ रुपये का लाभांश मिलने की उम्मीद जताई गई है। यह अंतरिम बजट के अनुमान 1.02 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले दोगुना से ज्यादा है।

इसमें यह भारी वृद्धि आरबीआई से 2.11 लाख करोड़ रुपये का लाभांश मिलने के कारण की गई है। बजट में चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत प्राप्ति 50 हजार करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान को घटाकर 30 हजार करोड़ रुपये किया गया है।

बजट 2024: अनुभव पर आधारित व्यावहारिक बजट

परिवहन विशेष न्यूज

लोकसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रहा था। विपक्ष की ओर से इसे केंद्रित करते हुए लुभावने वादे भी किए गए थे। अगले कुछ महीनों में तीन-चार राज्यों में चुनाव भी है जिसके नतीजे राजनीति के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी अहम होंगे। ऐसे में पहले बजट में मोदी सरकार ने रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा तत्परता दिखाई है।

नई दिल्ली। डेढ़ महीने पहले जो चुनावी नतीजे आए उसके बाद बजट को लेकर कुछ बातें बहुत स्पष्ट थीं। यह तय माना जा रहा था कि सरकार रोजगार तेजी से बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। इसके लिए जरूरी होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान बढ़ेगा। यह भी होना ही था मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिले और बिहार और आंध्र प्रदेश के अहम सहयोगियों जदयू और टीडीपी की आर्थिक जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। यह सब हुआ।

यह चुनावी नतीजों के अनुभव का निचोड़ है। लेकिन एक और बात जिसमें सरकार के दस साल का अनुभव दिखा वह है -बड़े सुधारों की घोषणा से बचते हुए राज्यों को साथ लेकर चलने का। दरअसल यही सच्चाई है कि राज्य जबतक केंद्र के साथ कदमताल नहीं करेंगे, देश का सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्हें एक मंच पर आना या लाना ही होगा। इसकी ठोस शुरूआत होती दिख रही है। यही कारण है कि मोदी सरकार की पुरानी छवि से इतर इस बार बड़े और सख्त सुधारों की बजाय बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए राज्यों को प्रेरित करने की कोशिश हो रही है।

लोकसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रहा था। विपक्ष की ओर से इसे केंद्रित करते हुए लुभावने वादे भी किए गए थे। अगले कुछ महीनों में तीन-चार राज्यों में चुनाव भी है जिसके नतीजे राजनीति के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी अहम होंगे। ऐसे में पहले बजट में मोदी सरकार ने रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा तत्परता दिखाई है। यह सच्चाई है कि सरकारी नौकरियां बहुत नहीं बढ़ सकती हैं लिहाजा निजी सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल हुई है।

यह जरूरी था क्योंकि कोई देश नहीं बढ़ सकता अगर युवा परेशान हो और अब दावा किया जा रहा है कि अगले पांच साल में चार करोड़ रोजगार का सृजन होगा। जरूरत इसके लगातार मानीटरग की होगी क्योंकि इसके लिए लगातार निजी सेक्टर की परेशानियों को दूर भी करना पड़ेगा। श्रम सुधार पर तेज कदम बढ़ते तो और रोजगार सृजन में और तेजी आ सकती थी लेकिन सरकार थोड़ी ठिठकी नजर आ रही है।

हालांकि यह भी सच्चाई है कि इसे बहुत दिन तक रोका नही जा सकता है। आज या कल सरकार को इसे बढ़ाना ही होगा।

मध्यम वर्ग अर्से से नाराज था कि उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। टैक्स में राहत दे दी गई। हालांकि यह राहत छोटा है लेकिन सरकार ने यह संदेश दे दिया है कि वह आगे भी कुछ करना चाहती है। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कुछ न कुछ होगा। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष घोषणाओं का राजनीतिक पहलू भी है लेकिन यह भी सच्चाई है कि इन्हें विशेष मदद की जरूरत है। वैसे इन घोषणाओं के बाद इन दोनों राज्यों की तरह से जैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके बाद एक अंश भी संशय नहीं है सरकार पूरी तरह स्थायी है। लेकिन भविष्य में सरकार को विशेष मदद के लिए कमर कस कर तैयार रहना होगा।

अनुभव ने सरकार को बता दिया है कि कृषि सुधार, भूमि सुधार और अधिग्रहण जैसे जरूरी लेकिन विवादित सुधार कार्य शुरू नहीं किए जा सकते हैं। लिहाजा राज्यों की राह ली गई है। पूरे बजट से जो सार निकलता है वह यह है कि राज्यों के रास्ते से ही सुधार अपनाए जाएंगे। आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाकर आगामी सुधारों के नये लक्ष्य तय किए जाएंगे। सुधार करने वाले राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने की व्यवस्था हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही भी कि सरकार उत्पादकता में सुधार व बाजारों व क्षेत्रों को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए सुधार करेगी।

इनमें भूमि, श्रम, पूंजी क्षेत्र में सुधार भी शामिल है। इनमें से कई सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग व आम सहमति आवश्यक है क्योंकि राज्यों के विकास से ही देश का विकास संभव है। केंद्र व राज्य मिल कर जो सुधार करेंगे उनमें प्रमुख है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार। कुछ बातें चकित करती हैं।

निर्मला सीतारमण ने रक्षा, गृह, शिक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य जैसे मंत्रालयों से संबंधित किसी मुद्दे पर घोषणा तो दूर उनकी उपलब्धियों तक पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। ऐसा क्यो? यह सच है कि कुछ घटनाओं को लेकर कुछ मंत्रालयों के नाम से भी विपक्ष एकबारगी उग्र हो रहा है। लेकिन इतने भर से रक्षात्मक होने की जरूरत तो नहीं दिखती। हो सकता है यह भी अनुभव का हिस्सा हो।

निकायों के सुधरे बिना नहीं संवरेंगे शहर लैंड रिकार्ड के डिजिटाइजेशन पर रहेगा जोर

परिवहन विशेष न्यूज

शहरी मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार लैंड रिकार्ड का डिजिटाइजेशन निकायों को संपत्तियों के रिकार्ड रखने में सहायता करेगा लेकिन सवाल यह है कि राज्य सरकारें क्या निकायों को यह अवसर और अधिकार देंगी कि वे अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला कर सकें। क्या वे शहरों के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करने के लिए तैयार हैं। शहरों के विकास के लिए साहसिक परिकल्पना की जरूरत है।

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी विकास को उन नौ क्षेत्रों में गिनाया जो देश की प्रगति और आर्थिक विकास का स्तंभ साबित होने जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई ठोस खाका, खासकर बुनियादी सुधार की बातें कम से कम उनके बजट भाषण में नजर नहीं आईं। वित्तमंत्री ने शहरों में लैंड रिकार्ड यानी जमीन के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का अवश्य एलान किया। जीआइएस मैपिंग के साथ यह रिकार्ड शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन बढ़ाने में सहायक साबित हो सकता है।

शहरी मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार लैंड रिकार्ड का डिजिटाइजेशन निकायों को संपत्तियों के रिकार्ड रखने में सहायता करेगा, लेकिन सवाल यह है कि राज्य सरकारें क्या निकायों को यह अवसर और अधिकार देंगी कि वे अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला कर सकें। क्या वे शहरों के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करने के लिए तैयार हैं। शहरों के ढांचे पर निगाह रखने वाले संगठन जनाग्रह के पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट प्रमुख प्रभात कुमार कहते हैं कि शहरों के विकास के लिए शून्य से सोचना होगा। केंद्र के पास शहरी विकास का एक विजन है, लेकिन यही बात राज्यों के लिए नहीं कही जा सकती।

शहरों के विकास के लिए साहसिक परिकल्पना की जरूरत है। तमाम दूसरे देश अर्बन प्लानिंग में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम एक आदर्श शहर नहीं बना पा रहे हैं, जिसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। शहरों का विकास राज्यों का विषय है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, खासकर अपने निकायों की जवाबदेही और उनके उत्तरदायित्व को लेकर। केंद्र सरकार ने दस साल में शहरी विकास के लिए बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन गौर कीजिए यह अभी भी कुल बजट का 1.7 प्रतिशत ही है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2030 में शहरों में रहने वाली आबादी 40 प्रतिशत से होगी।

यह आबादी बेहतर माहौल में जीने की हकदार है। प्रभात कुमार के मुताबिक इस बजट में ही शहरी विकास के लिए कुल आवंटन का 67 प्रतिशत केवल दो मदों के लिए है-पीएम आवास योजना और मेट्रो ट्रांजिट। जाहिर है, शहरी विकास के दूसरे विषय प्राथमिकता में छूट जाते हैं। केंद्र सरकार इस पर जोर दे रही है कि राज्य शहरी सुधारों को अपनाएं। उन्हें सहायता भी इसी कसौटी पर निर्भर की गई है, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे हैं। जमीन के रिकार्ड के डिजिटाइजेशन पर वर्षों से ध्यान नहीं दिया जा रहा।

इस डिजिटाइजेशन के बिना वे न तो राजस्व अर्जित कर पा रहे हैं और न ही अपने नागरिकों को सुविधा दे पा रहे हैं। शायद अब वे 1150 करोड़ रुपये राष्ट्रीय अर्बन डिजिटल मिशन के सहारे आगे बढ़ें। उन्हें स्टैंप ड्यूटी को भी तार्किक बनाना होगा।

शहरी विकास के लिए प्रमुख खर्च

- मेट्रो प्रोजेक्ट 24931 करोड़
- पीएम आवास योजना 30170 करोड़
- अमृत योजना 8000 करोड़
- पीएम ई बस सेवा 1300 करोड़
- स्मार्ट सिटी मिशन 2400 करोड़

ऊर्जा सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर, देश में लगाए जाएंगे छोटे व मॉड्यूलर परमाणु ऊर्जा संयंत्र

देश में ऊर्जा बदलाव के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की घोषणा की है जो यह बताएगा कि भारतीय इकोनमी में किस तरह से पारंपरिक ऊर्जा की जगह धीरे धीरे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का महत्व स्थापित होगा। यह दस्तावेज ऊर्जा सेक्टर में रोजगार विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी हल बताएगा। आयात सस्ता होने से इनका निर्माण भारत में करने में आसानी होगी।

नई दिल्ली। विकसित भारत बनने के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी शर्त है लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। सोलर, विंड इनर्जी को लेकर सरकार पहले ही काफी कुछ कर चुकी है अब फोकस परमाणु ऊर्जा और पम्पड स्टोरेज जैसे उन क्षेत्रों पर है जहां भारत बहुत ज्यादा संभावनाएं देख रहा है। आम बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऊर्जा सुरक्षा को इस बजट के नौ प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक दर्शाया।

उन्होंने देश में ऊर्जा बदलाव के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की घोषणा की है जो यह बताएगा कि भारतीय इकोनमी में किस तरह से पारंपरिक ऊर्जा की जगह धीरे धीरे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का महत्व स्थापित होगा। यह दस्तावेज ऊर्जा सेक्टर में रोजगार, विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी हल बताएगा। वित्त मंत्री ने बजटीय प्रस्ताव में निकेल, कोबाल्ट, कापर, लिथियम जैसे कुछ उत्पादों के आयात पर शुल्क घटाने का भी ऐलान किया है। इन उत्पादों का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा, सोलर ऊर्जा व दूसरे ऊर्जा क्षेत्रों में होता है।

आयात सस्ता होने से इनका निर्माण भारत में करने में आसानी होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि परमाणु उर्जा, रिनीवेबल ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले 25 आवश्यक धातुओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जबकि दो उत्पादों पर मूल आयात शुल्क (बीसीडी) को कर दिया गया है। वैसे इस कदम का फायदा इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों और बैट्री बनाने वाले सेक्टर को भी होगा। हाल के वर्षों में कुछ देशों में छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सफलता हासिल की है। वित्त मंत्री ने देश में भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना क रने, इसके लिए अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने की बात कही है।

इस सेक्टर में शोध व अनुसंधान के लिए केंद्र की तरफ से फंड दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया है कि बहुत ही प्रभावशाली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाने का स्वदेशी प्रौद्योगिकी भारत ने तैयार कर लिया है। पहली बार इसके तहत 800 मेगावाट क्षमता का एक प्लांट सरकारी क्षेत्र की एनटीपीसी और बीएचईएल मिल कर स्थापित करेंगे। इसके लिए आवश्यक राशि का इंतजाम सरकार की तरफ से होगा। यह पूरी तरह से भारतीय उत्पादों व प्रौद्योगिकी से तैयार बिजली संयंत्र होंगे जो कोयला आधारित होते हुए भी पर्यावरण को बहुत ही कम क्षति पहुंचाते हैं।

सिगरेट सहित सभी तम्बाकू उत्पादों पर नहीं बढ़ा टैक्स, ITC के शेयरों में जबरदस्त उछाल

2024 के Union Budget में तम्बाकू उत्पादों पर मौजूदा कर दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ऐसे होने से सभी तंबाकू उत्पादों सहित सिगरेट की कीमत अपरिवर्तित रहेंगी। सरकार के इस फैसले के बाद देश की सबसे बड़ी सिगरेट उत्पादक कंपनी ITC की शेयरों में 6.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) भी लगाती है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। 2024 के Union Budget में तम्बाकू उत्पादों पर मौजूदा कर दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ऐसे होने से सभी तंबाकू उत्पादों सहित सिगरेट की कीमत अपरिवर्तित रहेंगी।

ITC की शेयरों में जबरदस्त उछाल

सरकार के इस फैसले के बाद देश की सबसे बड़ी सिगरेट उत्पादक कंपनी ITC की शेयरों में 6.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ITC के स्टॉक 6.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 496.95 पर बंद हुए हैं।

ITC को सिगरेट के प्रोडक्शन पर बेहतरीन रेवेन्यू मिलता है। ये कंपनी की नेट प्रॉफिट में 80 प्रतिशत से अधिक और इसके कुल राजस्व में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान देता है।

तम्बाकू उत्पादों पर ऐसे लगता है टैक्स

तम्बाकू उत्पादों पर टैक्सेशन मुख्य रूप से माल और सेवा कर (GST) परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, केंद्र सरकार सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) भी लगाती है, जो केंद्रीय बजट के दौरान समायोजन के अधीन है।

अपने हालिया बजट संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तम्बाकू करों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया, पिछले वर्ष NCCD में 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पिछली बार बदली गई दरों को बनाए रखा है।

एमएसएमई को आसान कर्ज सुविधा, गुणवत्ता बढ़ाने में भी मदद

एमएसएमई को सबसे अधिक कठिनाई कर्ज लेने में ही आती है। इस बार के बजट में सरकार ने इस समस्या को दूर करने की कोशिश की है। कई बार एमएसएमई इसलिए भी अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि उनके पास नई मशीनरी खरीदने के लिए पूंजी नहीं होती है और बैंक बिना किसी गिरवी या थर्ड पार्टी गारंटी के उन्हें मशीनरी के लिए जल्दी कर्ज नहीं देता है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश के जीडीपी और निर्यात दोनों में ही 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान देने वाले एमएसएमई को सबसे अधिक कठिनाई कर्ज लेने में ही आती है। इस बार के बजट में सरकार ने इस समस्या को दूर करने की कोशिश की है।

क्रेडिट गारंटी स्कीम लांच

कई बार एमएसएमई इसलिए भी अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनके पास नई मशीनरी खरीदने के लिए पूंजी नहीं होती है और बैंक बिना किसी गिरवी या थर्ड पार्टी गारंटी के उन्हें मशीनरी के लिए जल्दी कर्ज नहीं देता है।

इस बार बजट में मशीनरी की खरीदारी के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लांच की गई है। इस स्कीम के तहत सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा जिसके तहत 100 करोड़ तक के लोन की गारंटी होगी।

MSME को आसानी से मिलेगा लोन

कर्ज लेने वाले एमएसएमई को सिर्फ अपफ्रंट गारंटी फीस देनी होगी। डिजिटल ट्रांजेक्शन के आधार पर भी एमएसएमई को लोन दिए जाएंगे। बजट की घोषणा के मुताबिक बैंक एमएसएमई को डिजिटल लेनदेन के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें लोन देगा।

कई ऐसे छोटे उद्यमी है जो अकेले ही कारोबार करते हैं और उनके टर्नओवर का मूल्यांकन करना आसान नहीं होता है।

लेकिन वे डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं।

इस प्रकार के उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा। कारोबारी परेशानी की वजह से एमएसएमई का कारोबार कई बार दिक्कत में आ जाता है और वे बैंक के कर्ज को नहीं चुका पाते हैं। एक से अधिक किस्त नहीं चुका पाने पर उनका खाता स्पेशल मेंशन खाता बन जाता है और वे एनपीए घोषित होने के कगार पर आ जाते हैं। ऐसा होने पर उन्हें बैंक से भविष्य में कर्ज नहीं मिलने में कठिनाई होती है।

एमएसएमई को इस परेशानी से बचाने के लिए अलग से फंड बनाने की घोषणा की गई है। वहीं एमएसएमई से जुड़े सभी बड़े क्लस्टर में अगले तीन साल में सिडबी अपनी शाखा खोलेगा और सीधे तौर पर वहां के एमएसएमई को लोन देगा। इस साल 24 ऐसी शाखा खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

एमएसएमई के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ जाने पर उन्हें काफी फायदा हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य आइटम से जुड़े एमएसएमई सेक्टर में उनकी गुणवत्ता जांच को लेकर 50 यूनिट खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

एमएसएमई इन दिनों 45 दिनों के भीतर भुगतान के नियम से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी खरीदारी के 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर बकाया राशि उद्यमी की आय बन जाती है और उस पर टैक्स लग जाता है। एमएसएमई 45 दिन की अवधि को बढ़ाकर 90 दिन करने की मांग कर रहे थे, लेकिन बजट में उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया।

बजट 2024: इस साल भी जनगणना की संभावना नहीं, बजट में सिर्फ 1309 करोड़ रुपये आवंटित

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार ने बजट में जनगणना के लिए सिर्फ 1309 .46 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। मगर जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की संभावना है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि इस साल भी जनगणना होने की उम्मीद नहीं है। बता दें कि 2020 में जनगणना का काम पूरे देश में होना था।

नई दिल्ली। जनगणना की संभावना इस वर्ष भी नहीं दिख रही है, क्योंकि बजट में इसके के लिए सिर्फ 1,309.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह 2021-22 की तुलना में काफी कम है। उस समय जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 24 दिसंबर, 2019 को हुई बैठक में 8,754.23 करोड़ रुपये की लागत से 2021 की जनगणना कराने और 3,941.35 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं

गौरतलब है कि जनगणना और एनपीआर का काम एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक पूरे देश में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। जनगणना कार्य अब भी रुका हुआ है और सरकार ने अभी तक इसके लिए नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है।

पिछले साल 578.29 करोड़ रुपये का हुआ था आवंटन

अधिकारियों ने बताया कि चूंकि इस वर्ष आम चुनाव हो चुके हैं, इसलिए 2024 में जनगणना का कार्य नहीं हो सकेगा। बजट 2024-25 के अनुसार, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी के लिए 1,309.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2023-24 में 578.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

जनगणना पर आएगा हजारों करोड़ का खर्च

अधिकारियों ने बताया कि पूरी जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर सरकार को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की संभावना है। यह कार्य जब भी होगा तो यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, जो नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर प्रदान करेगी।

बुजुर्गों के लिए आयुष्मान का अब भी इंतजार, कैंसर की तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह समाप्त

बुजुर्गों को आयुष्मान भारत का लाभ और सरवाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण को शामिल नहीं किये जाने से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी हैरान हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि कैंसर के मरीजों को राहत देने के लिए मैं तीन और दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करती हूं।

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए इस बार के बजट में एक घोषणा जो तय मानी जा रही थी वही नहीं हुई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाले तीन दवाओं को आयात कर से पूरी तरह से मुक्त कर कैंसर मरीजों को राहत जरूर दी। लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपये तक सालाना मुफ्त की इलाज की सुविधा देने का वायदा भी बजट का हिस्सा नहीं बन सका।

इसी तरह से बच्चियों को सरवाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान को हरी झंडी की मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसके लिए भी अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नई योजनाओं के शामिल नहीं किये जाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी हैरान हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्हें 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान भारत में शामिल किये जाने और सरवाइकल कैंसर के टीकाकरण अभियान शुरू किये जाने के बजट में एलान की पूरी उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि इसके पीछे के कारण को बताने में अपनी असमर्थता जताई।

इलाज पर खर्च की सीमा में संशोधन की मांग

ऐसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉक्टर गिरिधर ज्ञानी ने भी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत में शामिल नहीं किये जाने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत इलाज पर खर्च की सीमा में संशोधन की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन बजट में इसपर भी ध्यान नहीं दिया गया।

स्वास्थ्य बजट में इन चीजों पर रहा फोकस

वित्तमंत्री ने कैंसर की तीन दवाइयों को आयात कर से मुक्त करने के अलावा एक्सरे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स बेसिक कस्टम ड्यूटी में परिवर्तन का एलान किया। इसका उद्देश्य एक्सरे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स के देश के भीतर निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य बजट में सबसे अधिक बढ़ोतरी बायोटेक्नोलाजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हुआ है। इसके लिए बजट 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का बजट भी बढ़ाकर 65 करोड़ रुपये 90 करोड़ रुपये किया गया है। लेकिन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का बजट 200 करोड़ रुपये पर स्थिर है।

सम्बल पुर पुरी इंटरसिटी ट्रेन की यात्री का दर्द कौन समझेगा

मनोरंजन सासमल, स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेश्वर : पुरी से सम्बल पुर जाने बली ट्रेन (18303/18304) पुरी सम्बल पुर इंटरसिटी एक्सप्रेस मे यात्री का दर्द कोन दूर करेगा ! ट्रेन मे पैर रखने केलिए जागा नहीं। पुरुष और महिला यात्री निचे बैठ कर जा रही है। बचे, महिला और बुजुर्ग लोग लैट्रिन का पास निचे बैठ कर यात्रा कर रहा है ।यात्री का दाबे कर रहा है की और एक ट्रेन चलाना है। इसी ट्रेन का टाइमिंग भी ठीक नही है, एक दिन भी राइट टाइम पर नहीं आते हैं। 18303/18304 पुरी सम्बलपुर इंटरसिटी ट्रेन पच्छिम ओड़शिा की लाइफलाइन फिर भी ठीक टाइम पर अति नहीं जाति नहीं। रेल मंत्री को पब्लिक का दाबे है इसी ट्रेन को सही टाइम पर चलाए और एक नया ट्रेन चलाये।

बजट के विरोध में प्रदर्शन करेगा I.N.D.I.A, मल्लिकार्जुन खरगे के घर हुई बैठक में बनी सहमति

मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया। इसको लेकर विपक्ष के सभी नेताओं ने इस बजट पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए बुधवार को केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ किए गए भेदभाव को लेकर संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन करेगा। इस विरोध में कांग्रेस के साथ बाकी विपक्षी दल के नेता भी शामिल हो सकते हैं।

नई दिल्ली। विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए ने फैसला किया कि वह बुधवार को केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ किए गए भेदभाव को लेकर संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मंगलवार शाम आइएनडीआइए के घटक दलों के नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया।

ये नेता करेंगे विरोध प्रदर्शन

बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, राकांपा प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक-ओ-ब्रायन और कल्याण बनर्जी, द्रमुक के टीआर बालू, जेएमएम की महुआ माझी, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और संजय सिंह, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश, माकपा के जान ब्रिटास समेत कई नेता शामिल हुए।

वेणुगोपाल ने कही ये बात

वेणुगोपाल ने बैठक के बाद कहा कि इस साल के केंद्रीय बजट ने बजट की अवधारणा को पहले ही खत्म कर दिया है। उन्होंने अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया है। इसलिए आइएनडीआइए बैठक में यह आम सहमति थी कि हमें इसका विरोध करना चाहिए। बाद में एक्स पर पोस्ट में वेणुगोपाल ने कहा- "आज पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक था, जो संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के एकदम खिलाफ है, जिसका कि केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए।"

विरोध में कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सरकार का रवैया संवैधानिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि बजट ने उन राज्यों को अंधकारमय बना दिया है जहां गैर-भाजपा सरकारें हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हम इस संबंध में कल संसद में विरोध प्रदर्शन करेंगे।

क्या है एंजल टैक्स, जिसे सीतारमण ने किया खत्म 2012 में कांग्रेस सरकार ने क्यों लगाया था?

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट 2024 में एंजल टैक्स को समाप्त करने का एलान किया है। इस टैक्स को 2012 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने लगाया था। जानकारों के मुताबिक एंजल टैक्स खत्म करने के बाद स्टार्टअप आसानी से फंड जुटा सकेंगे। इससे स्टार्टअप में रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा।

नई दिल्ली। सरकार ने बजट में एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है। इससे स्टार्टअप को बड़ी राहत मिली है। संप्रग सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2012 में एंजल टैक्स लगाया गया था, जिसे स्टार्टअप अपने विकास में बड़ी बाधा मान रहे थे। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनोवेशन की जरूरत है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एंजल टैक्स को हटाने का फैसला किया गया है।

क्या है एंजल टैक्स?

जब कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते हुए उस पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता है, जिसे एंजल टैक्स कहा जाता है। अपनी फेयर वैल्यू से जितनी अधिक राशि स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से जुटाता है, उस पर एंजल टैक्स वसूला जाता है।

मान लीजिए किसी स्टार्टअप की फेयर वैल्यू एक करोड़ है और वह 1.5 करोड़ रुपये एंजल निवेशकों से जुटाता है तो 50 लाख रुपये पर एंजल टैक्स लगेगा।

एंजल टैक्स खत्म होने से क्या होगा फायदा?

वर्ष 2012 में टैक्स लगाते समय सरकार की यह सोच थी कि बाहरी निवेश की आड़ में मनी लॉन्डरिंग की जा सकती है। जानकारों का कहना है कि एंजल टैक्स को समाप्त करने से स्टार्टअप को फंड जुटाना आसान हो जाएगा। स्टार्टअप अब इनोवेशन पर अधिक खर्च कर सकेंगे और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। एंजल टैक्स की वजह से नए स्टार्टअप को फंड जुटाने में कठिनाई होती थी और विदेश से फंड जुटाने वालों को शक की नजर से देखा जाता था।

विवाद से विश्वास स्कीम 2024 लॉन्च

इनकम टैक्स से जुड़े विवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने फिर से विवाद से विश्वास स्कीम 2024 लांच करने की घोषणा की है। चार साल पहले भी विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर व सर्विस टैक्स संबंधित 60 लाख रुपये तक के विवाद पर टैक्स ट्रिब्यूनल में दो करोड़ के विवाद के लिए हाईकोर्ट में तो पांच करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है।

बजट में टैक्स संबंधी प्रविधान को और सरल बनाने का भी एलान किया गया है। इसके तहत पुराने रिटर्न का फिर से मूल्यांकन हो सकेगा। हालांकि सिर्फ 50 लाख या इससे अधिक राशि वाले कर मामले में ही तीन साल से उससे अधिक पुराने मामले का फिर ले मूल्यांकन होगा।

कर सरलीकरण प्रक्रिया की पहल

धर्मार्थ संस्थाओं और टीडीएस के लिए कर सरलीकरण प्रक्रिया की पहल करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अनेक भुगतानों पर पांच प्रतिशत टीडीएस दर को घटाकर दो प्रतिशत टीडीएस दर किया जा रहा है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को एक प्रतिशत से कम करके 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

टीसीएस की राशि को वेतन पर कटौती किए जाने वाले टीडीएस की गणना में लाभ दिए जाने का प्रस्ताव भी लाया गया है। जीएसटी के तहत सभी बड़ी करदाता सेवाओं और सीमा शुल्क तथा आयकर के अधीन ज्यादातर सेवाओं को डिजिटल रूप में लाने के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा शुल्क और आयकर की सभी शेष सेवाओं का अगले दो वर्षों के दौरान डिजिटाइजेशन किया जाएगा और उन्हें पेपर लेस बनाया जाएगा।

विकसित राष्ट्र भी और सधी राजनीति भी, 2.66 लाख करोड़ से बदलेगी गांवों की सूरत; खजाना भी मजबूत

बजट 2024 मंगलवार को पेश केंद्र सरकार के बजट में विकसित राष्ट्र और सधी राजनीति की झलक देखने को मिली। सरकार ने आंध्र प्रदेश और बिहार में खास फोकस किया है। वहीं गावों की सूरत भी बदलने का एलान किया है। तमाम घोषणाओं के बावजूद सरकार का खजाना भी मजबूत है। आने वाले पांच सालों में 4.10 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा।

नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी की सरकार 3.0 का पहला आम बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित करने और गठबंधन की राजनीति के बीच सामंजस्य बनाने की व्यावहारिक कोशिश है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकलुभावन घोषणाओं और बिग टिकट रिफॉर्म से परहेज किया है लेकिन आम मध्यम वर्ग को आय कर में कुछ छूट देकर और अगले पांच वर्षों में दो लाख करोड़ रुपये की मदद से 4.10 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की घोषणा के जरिए सरकार ने पिछले आम चुनाव में मनमाफिक परिणाम नहीं आने की वजहों को साधने की कोशिश की है।

नई सोच का सामने रखा

इसी तरह से बिहार व आंध्र प्रदेश से संबंधित घोषणाओं को आम बजट में प्रमुखता से शामिल होना गठबंधन सरकार की प्रकृति को भी दिखाता है। दूसरी तरफ सरकार राजकोषीय संतुलन स्थापित करने में पूरी तरह से सफल दिखती है और भूमि, श्रम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अटके पड़े आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए नई सोच को सामने रखा है।

पेश किया विकसित भारत का रोडमैप

वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। उनका बजट अभिभाषण सिर्फ 1.25 घंटे का रहा लेकिन यह फरवरी, 2024 में पेश अंतरिम बजट की सोच व नीतियों की निरंतरता को कायम रखने वाले हैं। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने आम बजट में विकसित भारत का विस्तृत रोडमैप पेश करना का वादा किया था और मंगलवार को उन्होंने यह किया भी।

सरकार ने तय की नौ प्राथमिकताएं

विकसित भारत के रोडमैप के तहत नौ प्राथमिकताएं तय की गई हैं जो हैं कृषि में उत्पादकता, रोजगार व कौशल प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, मैन्यूफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन (शोध व विकास) और अगली पीढ़ी के सुधार। गौर से देखा जाए तो इन सभी सेक्टरों में जो घोषणाएं की गई हैं, उनसें से अधिकांश सीधे या परोक्ष तौर पर रोजगार के अवसर को बढ़ाने वाले हैं।

वित्तमंत्री ने किया 57 बार रोजगार शब्द का इस्तेमाल

कोई आश्चर्य नहीं कि वित्त मंत्री के अभिभाषण में रोजगार शब्द का कुल 57 बार इस्तेमाल किया गया है। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में एसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने की बात हो या रोजगारपरक उद्योगों के लिए जरूरी कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाने का फैसला हो या ज्यादा रोजगार देने के लिए निजी सेक्टर को प्रोत्साहित करने वाली घोषणाएं हो या पांच वर्षों में उद्योग के मुताबिक 20 लाख प्रशिक्षित युवाओं को तैयार करने की घोषणा हो, ये सब रोजगार के मोर्चे पर उठ रहे राजनीतिक सवालों का जवाब दे सकते हैं।

दो लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार

रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अगले पांच वर्षों में कुल दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी और इससे 4.10 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होने का लक्ष्य रखा गया है। सनद रहे कि एक दिन पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2030 तक देश में हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत बताई गई है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने बजटीय प्रावधानों को लेकर कहा है कि, "इससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा और एक विकसित देश बन सकेंगे।"

एंजेल टैक्स होगा खत्म

पीएम ने युवाओं, वंचित वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को तवज्जो देने संबंधी उपायों की खास तौर पर प्रशंसा की है। ग्रामीण विकास के लिए बजट में 2.66 लाख करोड़ रुपये और ढांचागत विकास के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार की नीतिगत निरतंता को ही दिखाता है। वित्त मंत्री ने स्टार्ट अप सेक्टर पर लगाये जाने वाले एंजेल टैक्स को समाप्त करने का एलान किया है।

सोना-चांदी और मोबाइल होंगे सस्ते

मोबाइल फोन के साथ सोना और चांदी पर सीमा शुल्कि को घटा दिया है जिससे इनका आयात सस्ता होगा। मध्यम वर्ग को इस बात से भी राहत मिलेगी कि आयकर गणना में स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि को 50 से बढ़ा कर 75 हजार रुपये किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने वाले करदाताओं को औसतन 17,500 रुपये की कर बचत होगी। इसी तरह से पूंजीगत लाभ गणना को लेकर मौजूदा जटिल नियमों को आसान बनाया गया है।

बिहार और आंध्र प्रदेश को साधा

वित्त मंत्री ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास तौर पर घोषणाएं की हैं। बिहार की जदयू और आंध्र प्रदेश की टीडीपी केंद्र सरकार में प्रमुख सहयोगी दल हैं। दोनों दलों की तरफ से अपने अपने राज्यों के लिए विशेष पैकेज की मांग की जा रही थी जिसे एक तरह से बजटीय प्रावधानों से पूरा किया गया है। बिहार में एक्सप्रेसवे, बिजली परियोजना, हवाई अड्डों के निर्माण जैसे ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कुल 60 हजार करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा है जबकि आंध्र प्रदेश को केंद्र की मदद से 15 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दिलाई जाएगी।

सरकार पर 11.63 लाख करोड़ रुपये की उधारी

इस अतिरिक्त बोझ के बावजूद सरकार के खजाने की स्थिति बेहद मजबूत है और राजकोषीय घाटे को चालू वित्त वर्ष के दौरान 4.9 फीसद व अगले वित्त वर्ष 4.5 फीसद पर लाने को लेकर वित्त मंत्री पूरी तरह से आशान्वित हैं। आम बजट 2024-25 के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये और व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये का है। जबकि बाजार से उधारी 11.63 लाख करोड़ रुपये का है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023